04 - जनता के प्रति उत्तरदायी मीडिया की आवश्यकता

05 - आजाद जन्मे, आजाद जिए, आजाद मरे

A Daily News Magazine
इंदौर
गुरुवार, 23 जुलाई, 2026

06 - आरएनटीयू में राष्ट्रीय छात्र अध्ययन यात्रा का भावपूर्ण...

07 - कलेक्टर ने जिला परिवहन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 291, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

प्रसंगवश

नीतीश की जद यू: समाजवाद से सनातनवाद का सफर?

समी अहमद

वैसे तो बिहार में 'अयोध्या की तर्ज' वाली सोच समाजवादी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्त में ही जोर पकड़ चुकी थी, लेकिन 20 जुलाई को जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को अपनी राजनीति का आधार बताने वाले जनता दल यूनाइटेड के दो नेता 'सनातन स्वाभिमान' में सराबोर हो गए।

नीतीश कुमार बिहार को गरीब राज्य बताते थे लेकिन इस यात्रा के लिए बिहार सरकार ने अपने खजाने से ढाई करोड़ रुपए दिए हैं। जाने और लौटने के लिए दी गई ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशंड है। यात्रियों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो हर यात्री पर बिहार सरकार लगभग बाइस हजार रुपये खर्च कर रही है।

भारत सरकार और बिहार सरकार के सरकारी प्रतीक चिन्हों के साथ अनेक अखबारों में एक पूरे पेज के विज्ञापन में सोमनाथ यात्रा के 'शुभारंभ' का प्रचार किया गया था। इसे भारतीय संस्कृति, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बताते हुए लिखा गया था, 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्वः अटूट आस्था की गौरव गाथा।' इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री बीजेपी के सम्राट चौधरी की उपस्थिति तो चौंकाने वाली नहीं थी लेकिन जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव की 'गरिमामयी उपस्थिति' यह सवाल ज़रूर पैदा कर रही थी कि समाजवादी नेताओं की यह सनातनी यात्रा उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भगवाकरण का अंतिम चरण तो नहीं। ध्यान रहे कि चौधरी और यादव दोनों इस समय सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं।

वैसे, समाजवादी से सनातनी रंग में डूबने वाले ये दो नेता अकेले नहीं हैं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड का बड़ा धड़ा विचारधारा के स्तर पर पहले ही भगवाकृत हो चुका है। समाजवाद के नाम लेने वालों की यह सनातनी यात्रा दूसरे मामलों में भी भगवानकरण की मंजिलें तय कर रही हैं। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जारी इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान भी शामिल है, 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक हजार वर्षों की यात्रा का प्रतीक है, यह भारत के अस्तित्व और आत्मगौरव का उत्सव है।'

सरकार के इस विज्ञापन में इस यात्रा को भारतीय आत्मगौरव का शाश्वत विजय घोष बताया गया और लिखा गया, 'आइए, भक्ति, परंपरा और सनातन स्वाभिमान के इस अभियान में सम्मिलित होइए।'

दरअसल, बिहार सरकार की ओर से 1150 श्रद्धालुओं के जत्थे को एक स्पेशल ट्रेन से सोमनाथ की यात्रा पर भेजा जा रहा था। सरकार ने इसे एक बड़ा इवेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह पता नहीं चल सका कि इन 1150 'श्रद्धालुओं' का चयन किस आधार पर हुआ है लेकिन पहले यह बात बताई गई थी कि हर जिले के डीएम अपने स्तर से 20-25 ऐसे लोगों को चुनेंगे जो इस 'अटूट आस्था की गौरव गाथा' के 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के लिए 'सनातन स्वाभिमान की महायात्रा' में शामिल होना चाहते हैं। खबरों में बताया गया था कि यह यात्रा राज्य सरकार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहल का हिस्सा है। इसमें सरकार उनकी यात्रा के खर्च के अलावा, ठहरने और भोजन की व्यवस्था और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

इसी 15 जुलाई को बिहार सरकार ने श्रावणी मेला के प्रचार प्रसार के लिए 'आकर्षक पुरस्कार' योजना की घोषणा की है। अगर सोमनाथ यात्रा कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित है तो श्रावणी मेला में पुरस्कार देने की योजना पर्यटन विभाग की ओर से आई है। इसमें कहा गया है कि 'श्रावणी मेला 2026 के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन अनुभवों को अपने कमरे और रचनात्मकता के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएं और जीतें आकर्षक पुरस्कार।' इसके तहत पहला पुरस्कार तीन लाख, दूसरा दो लाख और तीसरा एक लाख रुपये का है। इसके अलावा दो प्रतिभागियों के लिए पचास हजार रुपये का चौथा पुरस्कार और पांच के लिए सांत्वना में पच्चीस हजार रुपये प्रति प्रतिभागी पुरस्कार की घोषणा की गई है।

इसके अलावा बिहार सरकार सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय अनुदान योजना भी चला रही है। इसके तहत सरकार लद्दाख की इस यात्रा पर आने वाले खर्च का 50 प्रतिशत और अधिकतम बीस हजार रुपये का अनुदान देगी। अधिकतम 100 तीर्थ यात्रियों के लिए यह योजना पहले 'आओ, पहले पाओ' के आधार पर है।

इसी तरह बिहार सरकार ने राज्य के 16 जिलों में 34 पर्यटन स्थलों का होमस्टे प्रोत्साहन योजना के लिए चयन किया है। इस योजना के बारे में अहम शिकायत यह है कि इसमें नीतीश कुमार के समय सीमित स्तर पर विकसित किए जाने वाले सूफी सर्किट का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इस योजना के तहत एक कमरे के लिए सरकार ने ढाई लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक हो सकती है।

समाजवादी से सनातनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका बिहार का शिक्षा विभाग भी निभा रहा है। बिहार सरकार ने पहले 551 मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की और बाद में उसका नाम चुपचाप सरस्वती विद्या निकेतन रख दिया जो आरएसएस के स्कूलों के नाम के अनुरूप माना जा रहा है। इन स्कूलों का रंग भी भगवा कर दिया गया। ध्यान रहे कि बिहार में पहले भी आदर्श विद्यालय के नाम से स्कूल खोले गए हैं लेकिन उनका रंग कभी ऐसा नहीं किया गया।

शुरू में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह जरूर कहा कि शिक्षा का कोई रंग नहीं होता। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि ये सारी योजनाएं बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के काम का संभालने के बाद शुरू हुई है लेकिन इसकी जड़ में 'अयोध्या की तर्ज' वाली सोच है। इसके अलावा कांग्रेस से जदयू में जाकर मंत्री पद लेने वाले और बाद में कुणाल किशोर के समधी बने नीतीश कुमार के खासम खास माने जाने वाले अशोक चौधरी का भी योगदान माना जाता है।

इससे पहले वह गया में फल्गु नदी में सालों भर पानी रखने की व्यवस्था के लिए एक डैम बनवा चुके थे जिस पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ और आज वहां सड़े हुए पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। हिंदू मान्यता के अनुसार फल्गु नदी को सीता जी का यह अभिशाप मिला था कि वह हमेशा अंतः सलिला रहेगी।

नीतीश कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से खुद को हमेशा दूर रखा लेकिन सीतामढ़ी के 'पुनौरा धाम' में मां जानकी मंदिर के विकास लिए नीतीश कुमार सरकार ने ही लगभग नौ सौ करोड़ रुपए दिए और उसके पहले से कहा जाने लगा था कि वहां 'अयोध्या की तर्ज' पर निर्माण होगा।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

वे कहीं नज़र नहीं आते
पर हर जगह मौजूद रहते हैं
दूध में घुली शक्कर की तरह नहीं
झाड़ी में छिपे साँप की तरह
या पेड़ के पीछे घात लगाए
बाघ की तरह
मैं लिखने के लिए क़लम उठाता हूँ
और घर पर पत्थरों के फिंकने की
आवाज़ आना शुरू हो जाती है
मैं बोलने के लिए मुँह खोलता हूँ
और खुद को एक उग्र भीड़ से घिरा
पाता हूँ
मैं पढ़ने के लिए किताब के पन्ने
पलटता हूँ
और घर की तलाशी लेने आए
भारी बूटों की धमक
दिल दहलाने लगती है
मैं उन पर बस एक निगाह डालता हूँ
और सड़क पर घसीट कर
मार डालने के दृश्य
आँखों के सामने तैरने लगते हैं
मैं खुद को एक अजनबी देश में पाकर
सर झुकाए
पीछे हाथ बाँधे
सड़क से गुज़रता हूँ
कभी-कभी यह भी
विरोध का एक तरीका
मान लिया जाता है।

- चंद्रशेखर साकल्ले

पीएम मोदी का एनडीए सांसदों को खास संदेश

- युवाओं का भरोसा जीतें, विपक्षी 'साजिशों' का पर्दाफाश करें

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए की बैठक में सांसदों से कहा कि युवाओं से संपर्क करें और उनकी चिंताओं को दूर करें और उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि विपक्ष कैसे 'डर' फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक में जो भी शामिल हैं, उन्हें ऐसी सजा मिले कि फिर ऐसी घटना न हो। एनडीए सांसदों की बैठक की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से एचटी ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें यह बताया गया है कि शिक्षा मंत्री

धर्मेंद्र प्रधान से नीट पेपर लीक की वजह से इस्तीफे की मांग को लेकर जो कुछ चल रहा है, उसको लेकर पीएम मोदी ने सत्ताधारी पक्ष के सांसदों से क्या कुछ कहा है। मंगलवार को हुई एनडीए बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, युवाओं का विश्वास जीतने की जरूरत है..पेपर लीक होने की वजह से उन्हें बहुत ही दिक्कतें हुईं, लेकिन दोबारा परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के करवाई गई। और धुरंधर वकीलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेपर लीक में जो भी शामिल हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।

छात्रों को विपक्ष की साजिशों के बारे में बताएं- पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय पार्टी की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसे 'मंगल मिलन' कहा जा रहा है। उन्होंने सांसदों से कहा कि छात्रों को भरोसा दिलाएं कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी और जो लोग भी पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। एक और व्यक्ति ने इस बैठक के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी राज्य गैंग्स के इस खतरे से अछूता नहीं है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 'उनमें से हर किसी को सजा मिले।' वे बोले कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और अब जरूरत आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की है।

धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, विधानसभा में भी लगे नारे, काली पट्टी बांधकर पहुंचे कांग्रेस विधायक

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुए पुलिस बर्ताव और छात्रों पर अत्याचार के विरोध में काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और बुधवार को इस सत्र का तीसरा दिन है।

इस बीच सदन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक-2026 और मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक-2026 पास कर दिया गया।

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पारितः उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि नए विश्वविद्यालयों में पदों पर भर्ती में कुछ समय लग रहा है।

सदन में चर्चा के बाद 3 बिल पास हुए

10 मिनट में प्रदर्शन खत्म, खंडेलवाल बोले- चेतावनी देने आए थे

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता रेडक्रॉस चौराहे पर पहुंचे। यहां से विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि दुबे और अन्य कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने रेडक्रॉस अस्पताल के सामने लिंक रोड पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया।इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और हाथों में लिए पोस्टर व तख्तियां पुलिस की तरफ फेंक दीं। करीब 10 मिनट तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए। मीडिया से बातचीत में हेमंत खंडेलवाल ने कहा, अभी तो हम चेतावनी देने आए थे।

विधायकों के हाथ में बंधी थी काली पट्टी

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक सदन पहुंचे और उन सभी के हाथ में काली पट्टी बंधी हुई थी। कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुए पुलिसिया बर्ताव और छात्रों पर हुए अत्याचार का विरोध कर रहे थे।

सरकार जवाब देने से बच रही

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि दिल्ली में अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। विधानसभा में इस पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन सरकार जवाब देने से बचती रही। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी और छात्रों पर अत्याचार, यही भाजपा सरकार की युवा नीति बन गई है।

मंत्री ने कॉकरोच कहकर उनका अपमान किया

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज विधानसभा में युवाओं और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुई बर्बरता को लेकर कांग्रेस विधायक दल ने हाथों पर काली पट्टी बांध प्रदर्शन किया और सरकार से जवाब मांगा। देश में अपने अधिकारों के लिए छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस आंदोलन को अस्थिरता फैलाना बताया और छात्रों को 'कॉकरोच' कहकर उनका अपमान किया।

मजाक उड़ाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

उन्होंने आगे कहा कि युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उनका मज़ाक उड़ाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीट पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी और छात्रों पर अत्याचार क्या यही भाजपा सरकार की युवा नीति है? हमारी मांग स्पष्ट है पेपर लीक पर चुप्पी तोड़िए, दोषियों पर कार्रवाई कीजिए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। यदि सरकार जवाबदेही तय नहीं कर सकती, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दीजिए।

पटना में उग्र हुए छात्र, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

- बनारस में कांग्रेसियों को उठाया, भोपाल में विधायक ने काली पट्टी बांधी

पटना (एजेंसी)। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के बाद देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए है। बुधवार को पटना पुलिस ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। जवाब में भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। जबकि, यूपी के बनारस में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस उठाकर ले गई। इधर, मध्य प्रदेश में विधानसभा से लेकर सड़कों तक विरोध देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। उधर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकभवन का घेराव किया। यूपी में लखनऊ समेत कई शहरों में सपा कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के ही नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में 40 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं।

'कॉकरोचों' पर लाठीचार्ज, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

चीफ जस्टिस बोले-वीडियो देखने का वक्त नहीं, हमारा समय बर्बाद न करें

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। बुधवार को एक वकील ने सीजेआई की अगुआई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका लगाई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।' जब वकील ने छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो देखने का दूसरी बार अनुरोध किया तो सीजेआई ने कहा, 'हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए।' बता दें कि 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था, कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। इस टिप्पणी के बाद ही अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अकाउंट बनाया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला था। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़े थे, इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और छात्रों को चोटें आई थीं।

सीजेपी बोली बात करना है तो सरकार जंतर-मंतर आए

- सीजेपी इस्तीफे पर अड़ी
- दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद, बंगाल से 2 हजार जवान बुलाए गए

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच सरकार ने दूसरी बार बातचीत की पेशकश की है। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा उनसे बात करना चाहते हैं और उन्हें उनके आवास पर बुलाया था लेकिन पार्टी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उधर, सुरक्षा के कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रों स्टेशन बंद कर दिए गए है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन का आज 33वां दिन है। यहां बुधवार सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हैं।

इनमें 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठियों, आंसू गैस के गोलों का शिकार हुए लोग भी पहुंचे हैं। इधर दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा पर अलग-अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज की हैं। प्रदर्शनकारियों पर RAF जवानों पर जानलेवा हमला, पथराव, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मंगलवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिले। वांगचुक 28 जून से अनशन पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता में भर्ती कराया गया है।

'छात्रों पर कार्रवाई न करने का भरोसा दे सरकार, खत्म कर दूंगा अनशन', सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से लिखी चिट्ठी

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर छात्रों पर कार्रवाई न करने का भरोसा मिले तो अपना अनशन खत्म करने को तैयार हूं। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के नाम चिट्ठी लिखी है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 23 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

1 किमी ड्रेनेज लाइन तैयार, पर बैकफ्लो का खतरा

हमीदिया रोड को डूबने से बचाने के लिए पीडब्ल्यू मुकरा तो मेट्रो ने उठाई कुदाली

भोपाल (नप्र)। राजधानी के सबसे व्यस्त व्यापारिक इलाके हमीदिया रोड को मानसून के पानी से बचाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की थी, लेकिन ऐन मौके पर पीडब्ल्यूडी ने हाथ खींच लिए। इसके बाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने खुद कमान संभाली और रेलवे ट्रैक के बगल से पात्रा नदी तक करीब 1 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन बिछाकर 24 चैंबर तैयार कर दिए।

मेट्रो टनल के दूसरे चरण का काम शुरू होने से पहले इस ड्रेनेज का बनना बेहद जरूरी था। हालांकि, मेट्रो के इस प्रयास के बाद भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। नाले का आउटलेट पात्रा नदी में खोला गया है, जहां तेज बारिश के दौरान नदी उफान पर आते ही पानी बैकफ्लो होकर वापस हमीदिया रोड की दुकानों और सड़कों पर आ सकता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब भी तेज बारिश होती है, पात्रा नदी का रूप देखने लायक (खतरनाक) होता है। इसने आसपास के निचले इलाकों में कई बार भारी तबाही और जलभराव फैलाया है। दो विधानसभाओं की राजनीति में फंसा ड्रेनेज का आउटलेट हमीदिया रोड का यह ड्रेनेज आउटलेट दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक खिंचाव का शिकार बन गया है। मेट्रो अधिकारियों ने पिछले दो महीनों में रात-दिन काम करके नाला तो बिछा दिया, लेकिन पानी के बहाव का रुख (पूर्व से पश्चिम का अंतर) तकनीकी रूप से अब भी सिरदर्द बना हुआ है।

अतिक्रमण और बेतरतीब खुदाई से बढ़ा संकट हमीदिया रोड पर लगातार हो रहे अतिक्रमण और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की खुदाई की वजह से पानी की निकासी का प्राकृतिक रास्ता बंद हो चुका है। अगर भारी बारिश हुई तो मेट्रो का यह अस्थाई इंतजाम नाकाफी साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार के अनुरूप विश्वविद्यालय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा से पारित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए विश्वविद्यालय व्यवस्था को अधिक सक्षम, प्रभावी और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में प्रदेश में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 33 हो गए हैं। इसी प्रकार एमबीबीएस सीटें 760 से बढ़कर 5,550 तथा स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें 140 से बढ़कर 2,862 हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 10 हजार तथा पीजी सीटों की संख्या 5 हजार तक पहुँचाना है, ताकि प्रदेश में डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

विश्वविद्यालय व्यवस्था होगी अधिक सक्षम- उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण विश्वविद्यालयों पर परीक्षा, मूल्यांकन, परिणाम, संबद्धता, शोध, नवाचार तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व भी लगातार बढ़ा है। संशोधन के माध्यम से विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और समयानुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को समयबद्ध एवं बेहतर शैक्षणिक सेवाएँ मिल सकेंगी।

भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मान- उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप विश्वविद्यालयों में कुलपति एवं प्रतिकुलपति के स्थान पर कुलगुरु एवं प्रति-कुलगुरु जैसे भारतीय परंपरा आधारित पदनाम अपनाए गए हैं। यह भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि संशोधन के माध्यम से कुलगुरु के चयन की प्रक्रिया को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है। अब स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले योग्य शिक्षाविद कुलगुरु पद के लिए पात्र होंगे। साथ ही केवल शासकीय संस्थानों तक सीमित पात्रता समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य शिक्षा विशेषज्ञों को भी अवसर उपलब्ध कराया गया है।

संक्षिप्त समाचार

आतंकी हमला, हेड कॉन्स्टेबल की मौत

● अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात थे, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली

श्रीनगर (एजेंसी)। कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में बुधवार को आतंकियों ने हमला किया। इसमें हेड कॉन्स्टेबल (35 साल) की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर करीब 12 :30 बजे आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक फायरिंग की। सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलीं। इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जख्मी हो गए।

रूसी हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत बर्दाश्त नहीं

विदेश मंत्री जयशंकर का रूसी विदेश मंत्री को दो टूक संदेश

मनीला (एजेंसी)। भारत ने रूस के सामने यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रूस के सामने उठाया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत की 'गहरी चिंता' दोहराई है। यह बातचीत तब हुई जब दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और अहम क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच ये बैठक उस वक्त हुई है जब MV गोल्डन लियो नाम के जहाज पर रूस ने हमला किया था।

हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे

धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को किया चैलेंज

हैदराबाद (एजेंसी)। नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को तेज कर दी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा। इस सब के बीच तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बड़ा हमला बोलते हुए सीधे पीएम मोदी को निशाने

पर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कोडंगल में प्रोटेस्ट को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 100 सालों से इस देश के गरीबों और युवाओं के लिए लड़ रही है। हम पहली बार लाठीचार्ज नहीं देख रहे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा हम देखेंगे कि आने वाले चुनावों में कौन जीतता है और कौन हारता है।

● खरगे की सरकार को दो टूक, राज्यसभा में रखी अपनी बात

पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा

...फिर करेंगे नीट पर चर्चा

राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, वे सदन में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा तभी चाहते हैं जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि सरकार पिछले तीन दिनों से लगातार NEET पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर रही है। लेकिन विपक्ष मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद बुधवार को काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे।

नड्डा बोले-संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, INDI गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर-जिम्मेदाराना है। हम संसद में उनके इस लोकतंत्र-विरोधी व्यवहार को साफ देख सकते हैं। संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी-अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा, हमारी सरकार NEET पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है।

विपक्ष युवाओं को राजनीतिक हथियार न बनाए : राजनाथ

राजनाथ सिंह ने कहा- दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और युवाओं को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और विवेकशील युवा ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली-भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्रनिर्माण के मार्ग को ही चुनेंगे। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो।

'पिछले एक दशक में 152 पेपर लीक हुए', राहुल गांधी बोले- शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जायज

नईदिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं के सड़क पर उतरने की वजह से दिल्ली का सियासी माहौल बेहद गर्म है। सीजेपी के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तमाम समर्थक जुटे हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मंगलवार रात को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार रात को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी सीजेपी के प्रदर्शन में पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री आवास के करीब धरने पर बैठ गए। इसे बीजेपी ने राजनीतिक तमाशा बताया है। राहुल और कांग्रेस के तमाम नेताओं के सड़क पर उतरने की वजह से नई दिल्ली का सियासी माहौल बेहद गर्म है।

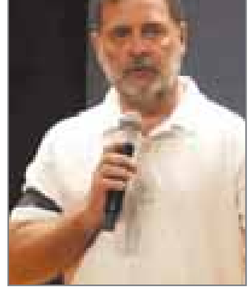

असम में हर ओर 'जल-जला' बाढ़ से बिगड़े हालात

● 16 जिलों में 5.64 लाख लोग प्रभावित, 21 लोगों की मौत और कई लापता

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के कई जिलों में लगातार बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। बाढ़ से 21 और लोगों की मौत हो गई और लगभग 5.65 लाख लोग प्रभावित हुए। मंगलवार आधी रात को जारी असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की रोजाना बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार, बिस्वनाथ, चराइदेव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलोंग, नागांव, शिवसागर और तिनसुकिया जिलों में 5,64,600 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसमें आगे बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में शिवसागर जिले में चार महिलाओं और दो बच्चों समेत 13 लोग बाढ़ के पानी में डूब गए। इसके बाद चराइदेव में दो बच्चों समेत पांच लोग, गोलाघाट में दो लोग और जोरहाट में एक महिला की मौत हुई। इन मौतों के साथ इस साल बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 31 हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने असम के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है।

हूती विद्रोहियों की धमकी से डर गए भारत और चीन

दोनों देशों के टैंकरों ने रास्ता बदला, सऊदी से तेल ला रहे थे

नई दिल्ली (एजेंसी)। सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर भारत और चीन जा रहे दो तेल टैंकरों ने मंगलवार को रेड सी (लाल सागर) में यू-टर्न लेकर अपना रास्ता बदल लिया। दोनों जहाज बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद वापस स्वेज नहर की ओर मुड़ गए। दरअसल, हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने दुनियाभर की शिपिंग कंपनियों को ईमेल भेजकर चेतावनी दी कि सऊदी अरब के किसी भी बंदरगाह पर माल लादने या उतारने वाले जहाजों को उनकी सैन्य पहुंच के भीतर कहीं भी निशाना बनाया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक, इनमें से एक सुपर टैंकर %शिन लॉन्ग यांग% सोमवार को सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर चीन के लिए रवाना हुआ था। जहाज मंगलवार सुबह बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट पहुंचने से पहले ही रुक गया और फिर यू-टर्न लेकर स्वेज रूट की तरफ मुड़ गए। भारत से जुड़ा दूसरा टैंकर भी इसी तरह अपना रास्ता बदलकर उत्तर की ओर चला गया।

होर्मुज बंद तो बाब अल-मंदेब पर निर्भर है सऊदी

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद सऊदी अरब अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल को रेड सी के यनबू बंदरगाह तक पहुंचाकर वहां से एशियाई देशों को भेज रहा है। अगर जहाज बाब-अल-मंदेब का रास्ता छोड़ते हैं, तो उन्हें स्वेज नहर और फिर अफ्रीका के लंबे समुद्री मार्ग का सहारा लेना पड़ सकता है। इससे यात्रा की दूरी हजारों मील बढ़ जाएगी, माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और भारत, चीन समेत एशियाई देशों तक तेल पहुंचने में अधिक समय लगेगा। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

ट्रम्प का दावा- ईरान बातचीत के लिए बेताब- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करना चाहता है, क्योंकि उस पर लगातार भारी दबाव पड़ रहा है। हालांकि अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने साफ किया कि जब तक ईरान किसी सार्थक बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका की मुलाकात में कोई रुचि नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने माना कि ईरान जॉर्डन में एक हमला करने में सफल रहा।

● चंपारण के 49 गांवों से गुजरेगा फोर लेन राम-जानकी पथ

अयोध्या से जनकपुर का सफर होगा बेहद आसान

मोतिहारी (एजेंसी)। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या व देवी जानकी के नगर जनकपुर को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी राम-जानकी पथ परियोजना अब पूर्वी चंपारण में गति पकड़ने लगी है। यह सड़क केवल परिवहन क्षेत्र की उपलब्धि नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से उत्तर बिहार की तस्वीर बदलने वाली मानी जा रही है। जिले में प्रस्तावित 56 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पांच सदस्यीय कमेटी की जांच अंतिम चरण में है। अधिसूचना व खेसरा पंजी के निर्माण को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। राम-जानकी पथ फोर लेन में बनना है। यह सड़क जिले के सात अंचलों के 49 राजस्व गांवों से होकर गुजरेगी। केसरिया के ढेकहां में यह सड़क जिले में प्रवेश कर पताही होते हुए शिवहर में प्रवेश करेगी। केसरिया अंचल के 11, कल्याणपुर के 15, चकिया के तीन, मेहसी के एक, मधुबन के 13, फेनहारा के पांच एवं पताही के एक राजस्व ग्राम से यह सड़क गुजरेगी। इससे इन गांवों के लोगों को बेहतर आवागमन का मार्ग मिलेगा, जिससे वहां की आर्थिकी बेहतर होगी।

● **नए रोजगार होंगे सृजित, बदलेगी आर्थिकी-** विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क निर्माण के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। सड़क किनारे होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, वे-साइड सुविधाएं और छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित होंगे। इससे हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भूमि की कीमतों में भी वृद्धि की संभावना है।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

राम-जानकी पथ का सबसे बड़ा लाभ धार्मिक पर्यटन को मिलेगा। अयोध्या से जनकपुर जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और तेज सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। प्रभु श्रीराम के नगर से जानकी नगर के बीच बन रही इस सड़क में विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप, सोमेश्वर धाम के दर्शन के बाद विराट रामायण मंदिर भी देखा जा सकेगा। कल्याणपुर के जानकी नगर में बन रहे विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का दर्शन भी लोग कर सकेंगे। ऐतिहासिक सीताकुंड जहां माता सीता व प्रभु श्री राम जनकपुर से विवाह के बाद वापस लौटने के क्रम में प्रवास किया था। यह स्थान भी इस सड़क से कनेक्ट होगा। वहीं सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर का दर्शन करते हुए जनकपुर धाम लोग जा सकेंगे।

ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन

भोपाल। रवींद्र भवन में दो दिवसीय सालाना ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस बार फिल्म फेस्टिवल में ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया फेलोशिप के चौथे बैच के फ़ेलोज द्वारा बनाई गई 15 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। इसके साथ संबन्धित विषयों परविशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान व विमर्श किए गए। ग्रीन हब एक रेज़िडेंशियल फेलोशिप है, जो भोपाल में संचालित होती है। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रसिद्ध लेखिका और फोटोग्राफर आरती कुमार राव थीं। विशेष वक्ता के तौर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आए अनुभव शौरी ने सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार समुदायों को मिल जाने के बाद पूरे समुदाय में आए सकारात्मक परिवर्तन पर अपने अनुभव साझा किए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) के सहयोग से बनी फिल्म सारस 'फ्रेंड ऑफ द फार्मर' सारस क्रेन पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार किसानों के सहयोग से इस दुर्लभ पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। एक अन्य फिल्म 'जंगलिया' ओडिशा के उन गांवों की महिलाओं की कहानी है, जो अपने जंगलों की रक्षा के लिए संगठित होकर कार्य कर रही हैं। इसी तरह एक फिल्म 'चांदाः धरोहर से भविष्य की ओर अत्री के सहयोग से 'मध्य के डिंडोरी व मंडला जिलों में आदिवासी समुदायों द्वारा अपने सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकारों की प्रक्रिया पर है। इस फिल्म फेस्टिवल की हर फिल्म किसी न किसी छोटी लेकिन प्रेरक सफलता की कहानी प्रस्तुत करती है और यह बताती है कि स्थानीय समुदाय किस तरह पर्यावरण और समाज से जुड़े मुद्दों के व्यावहारिक समाधान विकसित कर सकते हैं।

राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को सुप्रीम कोर्ट ने दी सरेंडर की सलाह

सोनम के वकील को दो विकल्प, जमानत पर फैसला कल होगा

इंदौर। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सोनम के वकील को सुझाव दिया कि वह आत्मसमर्पण कर जांच में सहयोग करे। मामले में अगली सुनवाई कल 23 जुलाई को होगी, जहां यह तय किया जाएगा कि सोनम की जमानत जारी रहेगी या उसे फिर जेल भेजा जाएगा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई में सोनम के वकील के सामने दो विकल्प रखे। पहला, यदि वे चाहें तो कोर्ट मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने वाली अपील पर उनकी दलील सुनकर अंतिम आदेश पारित कर सकती है। दूसरा, सोनम आत्मसमर्पण कर दे, ताकि जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकें। इसी दौरान जमानत के मुद्दे पर भी विचार किया जा सके।

हाईकोर्ट से मिली थी जमानत- इस वर्ष 23 अप्रैल को मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को जमानत दी थी। इसके बाद मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर अब सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की ओर से गिरफ्तारी को लेकर उठाए सवालों पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि यदि गिरफ्तारी के समय कारण नहीं बताए गए थे तो यह मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया। इस पर सोनम के वकील ने कोर्ट से समय मांगते हुए कहा कि वे निर्देश लेकर गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करेंगे।

मेघालय सरकार का विरोध- मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसने पुलिस के सामने पेश होकर आत्मसमर्पण किया था। ऐसे में यह दावा करना कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने बताया कि यदि गिरफ्तारी मेमो में कोई कमी है तो वह केवल लिपिकीय त्रुटि है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, वह बाद में गिरफ्तारी की तकनीकी प्रक्रिया को आधार बनाकर राहत की मांग नहीं कर सकता।

कारण बताना जरूरी नहीं

तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी के कारण अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति रंगेहाथ पकड़ा जाता है या स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है तो बाद में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि उसे गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया।

पेपर लीक, बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना

निष्पक्ष जांच, भर्तियां तेज करने की मांग, सिर मुंडाकर विरोध

इंदौर। चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के कथित प्रश्नपत्र लीक, कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया गया,वहीं कुछ छात्रों ने विरोध दर्ज कराने के लिए सिर मुंडवाकर नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि लगातार आंदोलन के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

छात्र प्रमोद नामदेव और छात्रा माही शर्मा ने कहा कि मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्षों तक आर्थिक संघर्ष करते हैं। ऐसे में यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, तो लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि युवाओं की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कर बेरोजगार युवाओं को न्याय देना चाहिए।

आईटी सेंटर से 9 बैटरियां चोरी

इंदौर। पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरी की वारदात कम नहीं हो रही है। सोमवार की दरमियानी रात बदमाशों ने तक्षशिला परिसर स्थित देवी अहिल्या विवि के आईटी सेंटर से यूपीएस सिस्टम की 9 बैटरियां चुरा ली। इसी प्रकार, जवाहरलाल नेहरू बालक छात्रावास में लगा 400 लीटर क्षमता का वॉटर कूलर व उससे जुड़ा आरओ सिस्टम बदमाश मामले में भंवरकुआं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, आईटी सेंटर प्रभारी रवींद्र शर्मा ने बताया कि 18 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे ड्यूटी के दौरान सुरक्षा गार्ड ने उन्हें चोरी की सूचना दी थी। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो आईटी सेंटर की विद्युत बैकअप प्रणाली से जुड़ी नौ बैटरियां गायब थी।

कल्याण ज्वेलर्स पर 1 लाख का स्पाट फाइन

इंदौर। बारिश का पानी सहेजने निगम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर जोर दे रहा है। सिस्टम के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, आवासीय इमारतों को नोटिस जारी किया है । इसके बावजूद सिस्टम लगाने को लेकर आमजन और व्यवसायी गंभीर नहीं है। नोटिस के बाद सिस्टम का अपडेट लेने निगम की टीम निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में निगम का अमला कल्याण ज्वेलर्स पहुंचा। यहां सिस्टम लगाने के लिए पूर्व में नोटिस दिया था। टीम को सिस्टम नहीं मिला तो मौके पर ही एक लाख रुपए का फाइन किया गया।

पुलिस जनसुनवाई में पहुंचे 79 फरियादी

इंदौर। पुलिस कमिश्नरेट में मंगलवार को जनसुनवाई में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने 79 आवेदनों पर सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में पारिवारिक विवाद, जमीन व मकान संबंधी धोखाधड़ी, आर्थिक ठगी, ब्लैकमेलिंग, वेतन नहीं मिलने, महिला अपराध और अन्य पुलिस संबंधी शिकायतें प्रमुख रहीं। पुलिस आयुक्त ने प्रत्येक आवेदक की समस्या गंभीरता से सुनते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मयंक अवस्थी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि शिकायतों के निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

स्मार्ट मीटर शिकायतों पर शिविर

इंदौर। स्मार्ट मीटर से अधिक बिजली खपत और बढ़े हुए बिलों की शिकायतों के समाधान के लिए मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सत्य साईं जोन ने तुलसी नगर स्थित सरस्वती मंदिर परिसर में विशेष समाधान शिविर लगाया। शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद 37 उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में संशोधन किया गया, जबकि 6 घरों में स्मार्ट मीटर की सटीकता जांचने के लिए समानांतर सामान्य मीटर लगाने का निर्णय लिया गया। तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर, निपनिया सहित आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं ने शिविर का लाभ उठाया। जोन प्रभारी के.पी. सिंह ने उपभोक्ताओं को बिजली की बचत और घरेलू उपकरणों के संतुलित उपयोग के उपाय भी बताए।

15 फीट ऊंचाई से गिरकर पेंटर की मौत

इंदौर। शहर और आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। आजाद नगर थाना क्षेत्र में पेंटिंग का काम कर रहे पश्चिम बंगाल निवासी मजदूर आशिक अहमद (पिता कादिर) की 15 फीट ऊंची टंकी से गिरने के कारण मौत हो गई। साथी करामत आलम के अनुसार, दोनों ठेके पर रंगाई-पुताई का काम करने इंदौर आए थे। काम के दौरान संतुलन बिगड़ने से आशिक नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, मानपुर क्षेत्र में दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है।

स्थापना दिवस पर 'चोइथराम' की सौगात

इंदौर। चोइथराम अस्पताल ने अपने 47 वें स्थापना दिवस के अवसर पर मरीजों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधा शुरू की है। योजना के तहत डॉक्टर से परामर्श कराने वाले मरीज 900 रुपये शुल्क पर कुल 2700 रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। परामर्श के साथ दो वाउचर दिए जाएंगे। एक वाउचर का उपयोग पैथोलॉजी जांच,एक्स-रे, एमआरआई, सोनोग्राफी,पीईटी स्कैन, फिजियोथेरेपी या विशेषज्ञ परामर्श में किया जा सकेगा, जबकि दूसरा वाउचर अस्पताल में भर्ती होने पर उपयोग होगा। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मरीजों को कम खर्च में बेहतर और समग्र उपचार उपलब्ध कराना है।

9 डेयरियों से 37 सैंपल, लैब भेजे गए, 3 जगह मोबाइल लैब से टेस्टिंग हुई

रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज की नियमित सफाई के निर्देश दिए

इंदौर। दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जांच अभियान चलाया। अभियान में 9 डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दूध, दही, पनीर, घी, मावा, मिठाई सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 37 नमूने लेकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए। वहीं 3 प्रतिष्ठानों पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से मौके पर ही प्रारंभिक जांच भी की गई।

खाद्य विभाग के सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी के अनुसार, सबसे पहले नेताजी सुभाष मार्ग स्थित मदनी दूध डेयरी एंड स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। यहां से मिश्रित दूध, पनीर, घी, दही, मलाई बर्फी और मिल्क केक के 6 नमूने लिए गए। निरीक्षण में पनीर और दही रखने वाला रेफ्रिजरेटर साफ-सुथरा नहीं मिला। अधिकारियों ने संचालक को नियमित सफाई रखने, निर्धारित तापमान पर खाद्य पदार्थों का भंडारण करने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए।

सांवरिया दूध भंडार, दौलतगंज से दूध और दही के 2 नमूने लिए गए। शिव शक्ति मिल्क एंड स्वीट्स सेंटर, स्कीम नंबर-78 से दूध, दही, पनीर और घी के 4 नमूने लिए गए। यहां मोबाइल लैब से मौके पर जांच भी की गई। अंबे डेयरी एंड स्वीट्स, अरण्य नगर से दूध के 4 और पनीर का 1 नमूना लिया गया। यहां भी मोबाइल लैब द्वारा प्रारंभिक जांच की गई।

श्री कृष्ण दूध-दही भंडार, स्कीम नंबर-78 से दूध, पनीर, मावा और घी के 4 नमूने लिए गए। जांच में सामने आया कि यहां राजगढ़ जिले के प्लांट से तैयार उत्पाद लाकर बेचे जा रहे हैं, जिनकी भी मौके पर जांच की गई। मां अंबे दूध-दही भंडार एंड किराना स्टोर, सुदामा नगर से दूध और दही के 2 नमूने लिए गए। पाटीदार डेयरी, देव नगर से दूध, दही, पनीर, मावा, घी और पेड़ा के 6 नमूने एकत्र किए गए। पूजा नमकीन, स्वीट्स एंड डेयरी, विदुर नगर से दूध, दही, पनीर, मावा और मिठाई के 5 नमूने लिए गए। कृष्ण नमकीन, स्वीट्स एंड एवरफ्रेश, विदुर नगर से दूध, दही और नमकीन के 3 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।

रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई

दो दिवसीय अभियान में लिए गए सभी 37 खाद्य नमूनों को जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिन नमूनों में गड़बड़ी या मिलावट पाए जाने की पुष्टि होगी, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मेट्रो दौड़ी नहीं, पहुंचा 8 करोड़ का बिल, निगम और मेट्रो आमने-सामने

17 स्टेशनों का अंतिम आकलन होने पर बढ़ सकती है वसूली

इंदौर। शहर में मेट्रो रेल का व्यावसायिक संचालन अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है,लेकिन नगर निगम और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच सेवा प्रभार को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर निगम ने गांधीनगर मेट्रो डिपो और पांच संचालित मेट्रो स्टेशनों के लिए वर्ष 2025-26 का सेवा प्रभार बकाया बताते हुए डिमांड लेटर जारी किया है।

निगम का दावा है कि सभी 17 स्टेशनों का अंतिम आकलन पूरा होने के बाद कुल देनदारी करीब 8 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। नगर निगम के अनुसार गांधीनगर डिपो पर मूल सेवा प्रभार 5 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि अधिभार जोड़ने के बाद यह राशि 7 करोड़ रुपये से ऊपर हो गई है। वहीं,पांच चालू मेट्रो स्टेशनों पर भी करीब 27 लाख रुपये से अधिक का सेवा प्रभार लंबित बताया गया है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में निगम सभी स्टेशनों और डिपो का अंतिम मूल्यांकन कर आगे की कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर,मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी नगर निगम से सेवा प्रभार संबंधी अपनी मांग रखी है,जिससे दोनों संस्थाओं के बीच वित्तीय दावों को लेकर स्थिति उलझ गई है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि जिन मेट्रो परिसंपत्तियों पर संपत्ति कर अथवा सेवा प्रभार देय है, उनकी मांग पहले भी भेजी जा चुकी है। यदि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से दर्ज आपत्तियां नियमों के अनुरूप सही पाई जाती हैं तो आवश्यक संशोधन किया जाएगा, अन्यथा नगर निगम की मांग यथावत रहेगी। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनने का इंतजार है।

नामांतरण घोटाले में उपायुक्त सगर को नगर निगम के राजस्व विभाग से हटाया

उपायुक्त केएस सगर और प्रदीप जैन के आईडी से हुए थे एक रात में 354 नामांतरण

इंदौर। इंदौर नगर निगम में सामने आए 354 कथित फर्जी नामांतरण प्रकरणों की जांच के बीच निगम प्रशासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने राजस्व विभाग समेत कई महत्वपूर्ण शाखाओं के प्रभार बदलते हुए नए आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई को निगम की धूमिल होती छवि सुधारने और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। आदेश के मुताबिक अब तक राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी कमिश्नर केशव सिंह सगर से यह प्रभार वापस लेकर डिप्टी कमिश्नर गरिमा पाटीदार को सौंप दिया गया है। वहीं केशव सिंह सगर को स्थापना शाखा और सेंट्रल स्टोर का दायित्व दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह बदलाव हाल ही में उजागर हुए 354 कथित फर्जी नामांतरण मामलों के बाद लगातार उठ रहे सवालों के मद्देनजर किया गया है।

इन मामलों में आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर संपत्तियों के नामांतरण किए गए, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगे। पूरे मामले की जांच जारी है और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन नामांतरण प्रकरणों की जांच चल रही है, वे उस अवधि के हैं जब तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर श्रृंगार श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर केशव सिंह सगर तथा पी.सी. जैन संबंधित दायित्वों पर पदस्थ थे। हालांकि, इस मामले में अभी किसी अधिकारी की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से तय नहीं की गई है और जांच पूरी होने के बाद ही प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी।

इधर, निगम प्रशासन ने अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया है। एडिशनल कमिश्नर आकाश सिंह को संपदा प्रबंधन एवं राजस्व वृद्धि सेल का प्रभार सौंपा गया है, जबकि अर्थ जैन को लीज शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम के भीतर इस फेरबदल को केवल नियमित प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राजस्व विभाग में जवाबदेही तय करने और जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

उत्कृष्ट कार्य करने पर 29 पुलिसकर्मी सम्मानित, पुलिस कमिश्नर का फोकस

अपराध नियंत्रण, नशा तस्करी पर कार्रवाई, अंधे कत्ल का खुलासा

इंदौर। आम नागरिकों को बेहतर और प्रभावी पुलिसिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की साप्ताहिक सम्मान योजना के तहत मंगलवार को 29 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया।

पलासिया स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार प्रदान कर सभी पुलिसकर्मियों के कार्यों की सराहना की। पुलिस आयुक्त ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ाता है और बेहतर पुलिसिंग के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने सभी सम्मानित अधिकारियों और कर्मचारियों से भविष्य में भी इसी समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। सम्मानित पुलिसकर्मियों में थाना राऊ के आरक्षक लोकेश को सड़क दुर्घटना प्रकरणों में ई-डीएआर के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया।

थाना सदर बाजार के आरक्षक अनिल अहिरवार और महेश नायक को प्रकरणों के प्रभावी निराकरण में योगदान के लिए सम्मान मिला। थाना विजय नगर की टीम को फर्जी मार्कशीट से जुड़े मामले में कार्रवाई कर आरोपी की गिरफ्तारी एवं दस्तावेज जब्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। थाना खजराना की टीम को 110 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर तस्कर की गिरफ्तारी,जबकि चंदन नगर पुलिस को अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा थाना रावजी बाजार और अपराध शाखा के पुलिसकर्मियों को आरोपियों की गिरफ्तारी तथा कोकीन बरामदगी जैसी प्रभावी कार्रवाई के लिए पुरस्कार दिया गया।

नामांतरण गड़बड़ी पर गुहार लगाई 'हमारा प्लॉट किसी और के नाम'

निगम आयुक्त बोले, शिकायतों की जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई

इंदौर। नगर निगम में सामने आए नामांतरण गड़बड़ी के मामलों के बीच मंगलवार को एक परिवार शिकायत लेकर निगम मुख्यालय पहुंचा। आरोप लगाया कि एयरपोर्ट रोड स्थित उनके प्लॉट का गलत तरीके से नामांतरण किया। वे वर्षों से प्लॉट-69 का संपत्ति कर जमा कर रहे हैं। रिकॉर्ड में नामांतरण प्लॉट क्रमांक 70 पर कर दिया गया, जिससे उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

परिवार ने बताया कि पिछले छह माह से वे निगम अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मामले का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर रिकॉर्ड में सुधार की मांग की है। उधर, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि जैसे ही बड़ी संख्या में नामांतरण संबंधी शिकायतों की जानकारी मिली, तत्काल रिकॉर्ड की जांच शुरू कर कई मामलों में सुधार किया गया। उन्होंने बताया कि पहले नामांतरण प्रक्रिया में ओटीपी सत्यापन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह प्रणाली लागू कर दी गई है।

निगम आयुक्त के अनुसार पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो सभी शिकायतों की पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रभावित लोगों की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

गैस पाइप धमाके में पार्षद पर भी केस

इंदौर। विजयनगर क्षेत्र में 23 जून को हुए अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले की जांच में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने नगर निगम पार्षद बालमुकुंद सोनी को भी प्रकरण में आरोपी बनाया है। इस संबंध में पुलिस ने मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जानकारी प्रस्तुत की। पुलिस के इस कदम के साथ ही मामले में आरोपियों की संख्या भी बढ़ गई है। पुलिस के अनुसार हादसे के समय पार्षद घटनास्थल पर मौजूद थे और बोरिंग के लिए स्थान तय करने में उनकी भूमिका सामने आई है। नगर निगम की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि संबंधित स्थान पर बोरिंग का कार्य कराया जा रहा था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। इससे पहले पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जांच की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया था कि यदि निष्पक्ष और प्रभावी जांच नहीं हुई तो प्रकरण किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए कई पहलुओं की दोबारा पड़ताल की। सुनवाई के दौरान बोरिंग मशीन और वाहन को सुपुर्द करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि जिला न्यायालय के आदेश के बाद ही संबंधित वाहन और मशीन सुपुर्द किए गए थे।

संपादकीय

मप्रः यूसीसी लागू होना स्वागतेय

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने विधानसभा में भारी हंगामे के बीच राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर न केवल संविधान बल्कि भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को भी पूरा कर दिया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही यह प्रदेश में लागू हो जाएगा। सरकार का यह कदम स्वागतेय है। वैसे भी भाजपा के तीन कोर मुद्दों में यूसीसी भी शामिल रहा है। पार्टी अब इसे भाजपा शासित राज्यों में टुकड़ों-टुकड़ों में लागू कर रही है। इस हिसाब से मप्र देश का चौथा राज्य है, जो यूसीसी को लागू करने जा रहा है। वैसे भी यूसीसी का प्रावधान संविधान में पहले से है। अगर विपक्ष और खासकर कांग्रेस व अन्य पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं तो इसके पीछे मुख्य रूप से मुस्लिम वोटों की चिंता है। क्योंकि मुसलमान ही मुख्य रूप से यूसीसी का विरोध यह कहकर कर रहे हैं कि यह उनके पर्सनल लॉ में दखल है। यूसीसी लागू करने के पहले राज्य सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने यूसीसी को लेकर बड़ी संख्या में आए सुझावों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की संरक्षा की गारंटी देते हैं। गौरतलब है कि यूसीसी का मुद्दा दशकों से देश में राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। हालांकि इसे स्वैच्छिक रखने की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश में अभी विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, लिव-इन संबंध और अन्य पारिवारिक मामलों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी कानूनों का समग्र अध्ययन कर एक समान, संतुलित और व्यावहारिक कानूनी व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। सरकार के मुताबिक यूसीसी के लिए किए गए जन परामर्श में 93 फीसदी लोगों ने इसका समर्थन किया। यूसीसी बिल के कुछ प्रमुख प्रावधानों में एक विवाह के बाद दूसरा विवाह तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक पहला विवाह कानूनी रूप से समाप्त न हो जाए, शामिल है। केवल तलाक, तलाक, तलाक कह देने से विवाह समाप्त नहीं होगा। तलाक तभी प्रभावी होगा जब कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी। जिन कानूनों में महिलाओं के अधिकार कम थे, वहां भाई और बहनों को समान अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन धार्मिक समारोह, अनुष्ठान और परंपराएं पहले की तरह जारी रहेंगी। विवाह का पंजीकरण पंचायत से लेकर नगरीय निकाय तक अनिवार्य होगा। न्यायालय के बाहर विवाह विच्छेद मान्य नहीं होगा। पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। महिलाओं को संपत्ति में वही अधिकार मिलेंगे जो पुरुषों को प्राप्त हैं। अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित रूढ़िगत समूहों को इस कानून से बाहर रखा गया है। अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लिव-इन संबंध के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अगर कोई व्यक्ति पहले से विवाहित है तो वह इस व्यवस्था के तहत लिव-इन संबंध में नहीं आ सकेगा। मौखिक तलाक या अनौपचारिक पंचायत के फैसलों को पूरी तरह गैर-कानूनी घोषित किया गया है। अब विवाह का समापन केवल कानून में बताए गए स्पष्ट और वैधानिक आधारों पर ही हो सकता है। शादी और तलाक तलाक के बाद उसी जीवनसाथी से दोबारा शादी करने के लिए 'निकाह हलाला' जैसी अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली शर्तों को मानना, बढ़ावा देना या मजबूर करना एक दंडनीय आपराधिक अपराध माना जाएगा। जहां भी यूसीसी लागू हुआ है, वहां कोई विवाद सामने नहीं आए हैं।

नजरिया

दिलीप लोकरे

लेखक स्तंभकार हैं।

जनता के प्रति उत्तरदायी मीडिया की आवश्यकता

सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले एक दिलचस्प लेकिन असहज करने वाला काल्पनिक सर्वे वायरल हुआ था। उसमें समुद्र के बीच फँसी एक नाव दिखाई गई थी, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, पुलिसकर्मी और पत्रकार सवार थे। नाव में केवल चार लोगों के लिए जगह थी। लोगों से पूछा गया कि नाव को बचाने के लिए किसे बाहर किया जाना चाहिए।

इस सर्वे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, लेकिन उसके नतीजे एक गंभीर सवाल जरुर खड़ा करते हैं । बड़ी संख्या में लोगों ने पत्रकार को नाव से बाहर करने का विकल्प चुना। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया प्रतिक्रिया नहीं थी। यह उस मानसिकता का संकेत थी जो आज समाज के एक बड़े हिस्से में मीडिया के प्रति बन चुकी है। कभी पत्रकार को समाज की आँख और कान माना जाता था, लेकिन आज वही पत्रकार और मीडिया संस्थान अविश्वास, संदेह और आलोचना के केंद्र में खड़े दिखाई देते हैं।

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका न्याय सुनिश्चित करती है। मीडिया का काम इन तीनों पर नजर रखना, जनता तक सही जानकारी पहुँचाना और सत्ता से सवाल पूछना है। इसलिए जब समाज का एक बड़ा वर्ग मीडिया पर भरोसा खोने लगे, तो यह केवल मीडिया का संकट नहीं रहता; यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य का प्रश्न बन जाता है।

आज मीडिया जगत का सबसे बड़ा तर्क आर्थिक मजबूरी है। समाचार पत्रों की छपाई, वितरण, चैनलों का संचालन, तकनीकी ढाँचा, रिपोर्टिंग नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म–इन सबकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया संस्थान कहते हैं कि केवल पाठकों या दर्शकों से मिलने वाली आय के आधार पर उनका संचालन संभव नहीं है, इसलिए उन्हें विज्ञापनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

यह तर्क पूरी तरह गलत भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्थिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए संपादकीय स्वतंत्रता का बलिदान दिया जा सकता है? क्या विज्ञापनदाता, कॉर्पोरेट समूह या राजनीतिक शक्तियाँ यह तय करेंगी कि जनता तक कौन-सी खबर पहुँचेगी और कौन-सी नहीं? यही वह बिंदु है जहाँ पत्रकारिता और व्यापार के बीच संघर्ष शुरू होता है।

भारतीय पत्रकारिता का इतिहास बताता है कि ऐसा हमेशा नहीं था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी भारतीय पत्रकारिता ने केवल खबरें प्रकाशित करने का काम नहीं किया, बल्कि वह स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन का एक सक्रिय और साहसी सहभागी बन गई थी। केसरी, मराठा, यंग इंडिया, हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, प्रताप और द हिंदू जैसे अनेक समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों को बेनकाब किया और स्वतंत्रता की चेतना को जन-जन तक पहुँचाया। उस दौर में पत्रकारिता कोई लाभ का व्यवसाय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य और जनसेवा का माध्यम मानी जाती थी। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे अनेक पत्रकारों और संपादकों ने जेल यात्राएँ कीं, मुकदमे झेले और आर्थिक कठिनाइयाँ सहीं, लेकिन सत्ता के सामने झुकने से इनकार किया। ब्रिटिश सरकार ने कई अखबारों पर प्रतिबंध लगाए, प्रेस जब्त किए और संपादकों को कारावास में डाला, फिर भी भारतीय प्रेस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की मशाल बुझने नहीं दी। भारतीय पत्रकारिता का यह स्वर्णिम अध्याय हमें याद दिलाता है कि मीडिया की वास्तविक ताकत उसकी तकनीक, पूँजी या पहुँच में नहीं, बल्कि उसके नैतिक साहस और जनहित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में निहित होती है। 1975 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सबसे कठिन दौरों में गिना जाता है। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। कई अखबारों को सरकारी दबाव का सामना करना पड़ा। कुछ संस्थान झुक गए, लेकिन कुछ ने प्रतिरोध भी किया। कुछ समाचार पत्रों ने विरोध स्वरूप अपने संपादकीय पृष्ठ खाली छोड़ दिए। वह खाली स्थान किसी भी लेख से अधिक प्रभावशाली था। उसने बता दिया था कि प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला हुआ है।

उस दौर की पत्रकारिता में कमियाँ थीं, लेकिन उसमें आत्मसम्मान भी था। पत्रकार जानते थे कि उनका पहला दायित्व सत्ता को खुश करना नहीं, बल्कि जनता को सच बताना है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भय, आक्रोश और असुरक्षा के माहौल से गुजर रहा था। उस समय भी अधिकांश प्रिंट मीडिया ने अपेक्षाकृत संयमित भूमिका निभाई। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं था, बल्कि समाज को टूटने से बचाना भी था।

फिर समय बदला। उदारीकरण के बाद मीडिया उद्योग का विस्तार हुआ। निजी चैनलों का दौर आया। चौबीस घंटे समाचार प्रसारित होने लगे। तकनीक ने पत्रकारिता को तेज, आकर्षक और व्यापक बनाया। यह परिवर्तन अपने आप में सकारात्मक था। लेकिन इसके साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। दर्शक संख्या और टीआरपी सफलता का मुख्य पैमाना बन गई। यहीं से पत्रकारिता का चरित्र बदलना शुरू हुआ। खबरें केवल सूचना नहीं रहीं; वे उत्पाद बन गईं। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। धीरे-धीरे तथ्य, विश्लेषण और संतुलन की जगह सनसनी, शोर और टकराव ने ले ली। टेलीविजन स्टूडियो बहस के मंच कम और प्रदर्शन के मंच अधिक बनते गए। ऐसी बहसें आयोजित की जाने लगीं जिनका उद्देश्य समाधान ढूँढ़ना नहीं बल्कि विवाद पैदा करना था। जितनी ज्यादा उत्तेजना, उतनी ज्यादा दर्शक संख्या; जितनी ज्यादा दर्शक संख्या, उतना ज्यादा विज्ञापन राजस्व। इस प्रक्रिया में पत्रकारिता का मूल उद्देश्य पीछे छूटता गया।

समस्या केवल मीडिया तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र के अन्य स्तंभ भी अपने-अपने संकटों से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में मीडिया की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही वह मंच है जहाँ इन सभी संस्थाओं से जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। लेकिन यदि मीडिया स्वयं राजनीतिक और आर्थिक हितों से प्रभावित हो जाए, तो जनता किस पर भरोसा करे?

यही कारण है कि मीडिया की साख का संकट आज इतना गहरा दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि कुछ मीडिया संस्थान खबरों का चयन भी वैचारिक झुकाव या व्यावसायिक हितों के आधार पर करते हैं। कुछ चैनलों पर आरोप लगते हैं कि वे सत्ता के पक्ष में खड़े हैं। कुछ पर आरोप लगते हैं कि वे केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। परिणाम यह हुआ कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे। डिजिटल युग ने इस संकट को और जटिल बना दिया है। सोशल मीडिया ने सूचना के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब केवल बड़े मीडिया संस्थानों के पास सूचना प्रसारित करने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ फर्जी खबरों, अफवाहों और दुष्प्रचार का खतरा भी बढ़ा है।

आज एक झूठी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुँच सकती है। डीपफेक तकनीक, भ्रामक वीडियो और संगठित ट्रोल अभियान लोगों की राय को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे माहौल में जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। विडंबना यह है कि जिस समय समाज को विश्वसनीय पत्रकारिता की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसी समय पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सबसे अधिक सवाल उठ रहे हैं लेकिन क्या स्थिति पूरी तरह निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के कई देशों में ऐसे मीडिया मॉडल विकसित हुए हैं जो पाठकों और दर्शकों के सहयोग पर आधारित हैं। वहाँ लोग अच्छी पत्रकारिता के लिए भुगतान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता की भी एक कीमत होती है। भारत में भी कुछ स्वतंत्र डिजिटल मंच इसी दिशा में प्रयोग कर रहे हैं।

मीडिया की विश्वसनीयता लौटाने के लिए सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है संपादकीय स्वतंत्रता की पुर्नस्थापना। समाचार का निर्णय संपादक करे, विपणन विभाग नहीं। खबर का महत्व उसकी सामाजिक उपयोगिता से तय हो, न कि उसके व्यावसायिक लाभ से। तीसरा, पत्रकारिता को फिर से तथ्य-जांच और सत्यापन की संस्कृति की ओर लौटना होगा। सबसे पहले खबर देने की होड़ में गलत खबर देने से बेहतर है कुछ देर बाद सही खबर देना। चौथा, मीडिया को समाज के वास्तविक मुद्दों पर लौटना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि, पर्यावरण, स्थानीय शासन और नागरिक अधिकार जैसे विषय किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। यदि ये मुद्दे सार्वजनिक विमर्श से गायब हो जाएँ, तो लोकतंत्र केवल राजनीतिक नारों तक सीमित रह जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया को जनता का विश्वास फिर से अर्जित करना होगा। विश्वास माँगा नहीं जाता, कमाया जाता है।

सोशल मीडिया के उस काल्पनिक सर्वे में यदि लोगों ने पत्रकार को नाव से बाहर करने की बात कही, तो यह मीडिया के लिए एक चेतावनी है। क्योंकि बिना स्वतंत्र मीडिया के भ्रष्टाचार छिप जाएगा, सत्ता निरंकुश हो सकती है। जनता तक सही जानकारी नहीं पहुँचेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही कमजोर पड़ जाएगी।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि मीडिया की जरूरत है या नहीं। सवाल यह है कि हमें कैसा मीडिया चाहिए। ऐसा मीडिया जो सत्ता का प्रवक्ता नहीं, जनता का प्रतिनिधि हो। ऐसा मीडिया जो शोर नहीं, तथ्य प्रस्तुत करे। ऐसा मीडिया जो डर के बजाय साहस और पूर्वाग्रह के बजाय सत्य को महत्व दे। और ऐसा मीडिया जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने की जिम्मेदारी को केवल एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व समझे। जब पत्रकारिता फिर से जनता के विश्वास के योग्य बनेगी, तब शायद समाज उसे नाव से बाहर फेंकने के बजाय उसके साथ मिलकर नाव को किनारे तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपेगा।

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस

डॉ. रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), भारत सरकार!

प्रसारण की भूमिका राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय

प्रसार भारती के नाम से प्रचलित भारतीय प्रसारण तंत्र आज विश्व का बससे बड़ा ब्रॉडकास्ट डिविजन है। 15 सिंतबर 1959 को, दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियों में, भारत का पहला टीवी चैनल शुरू किया गया था जो आज 'दूरदर्शन' यानी डीडी न्यूज के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसारण के विस्तार पर अगर नजर डालें, तो वर्तमान में आकाशवाणी के कुल 591 रेडियो केंद्र और प्रसारण के 230 स्टेशन संचालित हैं। वहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में इस समय 908 निजी सैटेलाइट टीवी न्यूज चैनल सार्वजनिक प्रसारण सेवा में हैं। इनमें 40 फीसदी यानी करीब 350-400 के बीच केवल समाचार श्रेणी के हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा विभिन्न राज्यस्तरीय भाषाओं में संचालित हैं। निजी प्रसारण में आगमन सबसे पहले 1992 में 'जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज' से हुआ, उसके बाद तो निजी क्षेत्र में प्रसारणों की बाढ़ आ गई। करीब 3 हजार से अधिक नए लाइसेंसों के लिए मंत्रालय में आवेदन आवेदित हैं।

भारत में 'राष्ट्रीय प्रसारण दिवस' प्रत्येक 23 जुलाई को मनाया जाता है। सूचना विधाओं के लिहाज से आज का दिन रेडियो क्रांति और प्रसारण का प्रतीक भी है। दिवस की शुरुआत वर्ष-1927 में हुई थी जिसका आज का 99वां संस्करण है। सर्वविदित है कि 23 जुलाई 1927 को 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' नाम से एक प्राइवेट संस्था ने 'बॉम्बे रेडियो क्लब' स्टेशन से हिंदुस्तान में पहला प्रसारण किया गया था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत द्वारा लाइसेंस प्राप्त थी। कुछ वर्षों बाद 'ऑल इंडिया रेडियो' और फिर आकाशवाणी के रूप में स्थापित हुई। वैसे, विधिवत रूप से प्रसारण मंच का शुभारंभ 8 जून 1936 से हुआ था। इसी दिन से विविध भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों को एक सूत्र में पिरोने का चलन आरंभ हुआ। आकाशवाणी का नाम प्रसिद्ध रचनाधर्मी 'एमबी गोपालस्वामी' द्वारा दिया गया था, जो संस्कृत शब्द से गढ़ा गया था। जिसका शाब्दिक मतलब होता है 'आकाश से आवाज'। इस शब्द को आधिकारिक रूप से 1935 में मैसूर में भारत के पहले निजी रेडियो स्टेशन की स्थापना के वक्त इस्तेमाल हुआ, जिसे बाद में भारत सरकार ने सार्वजनिक और आधिकारिक रूप से सरकारी रेडियो के लिए प्रयोग किया।

प्रसार भारती के नाम से प्रचलित भारतीय प्रसारण तंत्र आज विश्व का बससे बड़ा ब्रॉडकास्ट डिविजन है। 15 सिंतबर 1959 को, दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियों में, भारत का पहला टीवी चैनल शुरू किया गया था जो आज 'दूरदर्शन' यानी डीडी न्यूज के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसारण के विस्तार पर अगर नजर डालें, तो वर्तमान में आकाशवाणी के कुल 591 रेडियो केंद्र और प्रसारण के 230 स्टेशन संचालित हैं। वहीं, सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में इस समय 908 निजी सैटेलाइट टीवी न्यूज चैनल सार्वजनिक प्रसारण सेवा में हैं। इनमें 40 फीसदी यानी करीब 350-400 के बीच केवल समाचार श्रेणी के हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा विभिन्न राज्यस्तरीय भाषाओं में संचालित हैं। निजी प्रसारण में आगमन सबसे पहले 1992 में 'जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज' से हुआ, उसके बाद तो निजी क्षेत्र में प्रसारणों की बाढ़ आ गई। करीब 3 हजार से अधिक नए लाइसेंसों के लिए मंत्रालय में आवेदन आवेदित हैं।

भारत में प्रसारण का कलर 25 अप्रैल 1982 में बदला गया। यहीं से रंगीन टीवी की शुरुआत हुई, वरना इससे पहले तक पर्दा सफेद ही था। ये वह वक्त था जब दिल्ली में एशियाई खेलों का महाकुंभ आरंभ होना था। तब तेजी से वैश्विक स्तर पर मांग उठ रही थी कि खेलों का प्रसारण रंगीन पर्दे पर किया जाए। इसके बाद 'ब्लैक एंड व्हाइट' के दौर का अंत हुआ और टीवी का पर्दा रातों-रात कलरफुल हो गया। टीवी प्रसारण का मतलब होता है ऑडियो और वीडियो सामग्री को विधुत चुम्बकीय तरंगों जैसे केबल, सैटेलाइट या इंटरनेट के जरिए जन जन तक पहुंचाना। प्रसारण आज के समय में सभी के जीवन का हिस्सा बन गया है। प्रसारण ऐसी संचार प्रणाली है जो दर्शकों को घर बैठे न्यूज से लेकर मनोरंजन के सभी माध्यमों को परोसता है। हालांकि, तकनीकी विकास के साथ प्रसारण विधाओं में काफी बदलाव हुआ है। अब दर्शक केबल या सैटेलाइट यंत्रों पर ही निर्भर नहीं रहते। दर्शक डाटा खर्च करके मोबाइल से ही हर प्रकार के प्रसारण का लुफ्त उठा लेते हैं। फिर चाहे, मैच हो या समाचार।

प्रसारण के क्षेत्र में अब इंटरनेट, डिजिटल और ओटीटी ने और विस्तार कर दिया है। सरकार सालाना प्रसारण से विज्ञापनों और फ्रीडिश से करीब 1200 से 1600 करोड़ रूपए कमाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रसार भारती का कुल राजस्व 1643 करोड़ था जिसमें से प्रमुख हिस्सा सरकारी डीटीएच प्लेटफार्म का था। साल 2025 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय द्वारा बताया गया था कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने निजी विज्ञापनों से तीन साल यानी 2022 से 2025 के बीच कुल 587.78 करोड़ कमाए। वहीं, 2025-2026 के अतं तक 650 करोड़ कमाने का लक्ष्य प्रसार भारती ने रखा हुआ है। ये ऐसा लक्ष्य है जिसे भी आसानी से हासिल किया जा सकता है।

राष्ट्र निर्माण में प्रसारण की जो स्वर्णिम यात्रा सदियों पहले आरंभ हुई थी वह आज भी निरंतर जारी है। प्रसारण का क्षेत्र जनमानस के मन के तारों को छूता है। प्रसारण के जरिए ही बदलती तकनीकों के साथ संवाद भी निरंतर जारी हैं। केंद्र सरकार ने फ्री और निशुल्क चैनलों का वर्गीकरण भी बीते कुछ सालों से किया है, ताकि कोई भी दर्शक प्रसारण के रस से अछूता न रहे। 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' ऐसा प्रसारण नारा है जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रसारण परिंदों की भांति है जिसकी कोई सीमा और बंदिशें नहीं? केंद्र सरकार प्रसारण में नए रस घोलने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बदलाव करती है। मंनोरंजन के नए-नए कार्यक्रमों का शुभारंभ और समाचार की प्रस्तुतिकरण में समय-समय पर बदलाव किया जाता है, ताकी दर्शक बोर न हों। वर्ष-2012 से भारत सरकार ने मनोरंजन, समाचार, खेल, खेतीबाड़ी आदि क्षेत्रों में प्रसारण के विस्तार को बढ़ाया हैं। फ्री-डिश बिना किसी मासिक शुल्क के करीब 400 से अधिक चैनल शहरी-ग्रामीण दर्शकों को मुहैया करवाता है। यही कारण है भारतीय प्रसारण आज विश्व का बससे बड़ा प्रसारण क्षेत्र बनकर उभरा है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

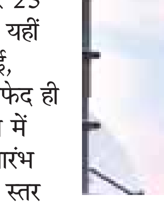

डॉ.महेन्द्र अग्रवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

गड्ढे में गड्ढा गड्ढे में गाड़ी

बारिश के आते ही सूखे गड्ढों के तन-मन हरे होने लगते हैं। उनका धरती में दबा छुपा रोम-रोम पुलकित होने लगता है। उन्हें लगता है कि उनके भी दिन फिरने वाले हैं और उनके भीतर का खालीपन अतिशीघ्र भरने वाला है ।वर्षा की पहली या दूसरी झाड़ी में ऐसा हो भी जाता है ।होना भी चाहिए,जब घूरे के भी दिन फिर जाते हैं तो गड्ढों के क्यों नहीं ? उनकी किस्मत क्या घूरे से,आम आदमी से,या मतदाता से भी बुरी है ? वर्षा से पहले सड़क पर चलने वालों को उन्हें देखने और उनसे बचकर चलने की सुविधा होती है किंतु वर्षा काल में यह सुविधा भी राहगीरों से परमात्मा या प्रशासन या दोनों मिलकर छीन लेते हैं। सड़क पर पानी भरा हो तो गड्ढों का सही अनुमान लगाना कठिन हो जाता है और आदमी असमंजस की स्थिति से गुजरते हुए पैदल चलते या वाहन सहित अनजाने में ही सही इसकी गहराई नापने उसमें उतर पड़ता है ताकि बाद वालों को उसकी जानकारी दे सके। यद्यपि उसका ऐसा कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता फिर भी परोपकार की इस अनुकरणीय क्रिया से उसके उतरने-निकलने के बाद कुछ लोगों को वहां गड्ढा होने की महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है।इसलिए स्थानीय प्रशासन को वहां उसके नाम की पट्टिका अवश्य लगवानी चाहिये कि फलां तारीख को फलां शख्स की

बदौलत जन सामान्य को इसकी जानकारी मिली। उसमें उनके शहीद होने या उनकी मुकम्मल टूट फूट की जानकारी भी दर्ज हो तो सोने में सुहागा। मैं तो ये कहूंगा कि राज्य शासन को इसके लिए अलग से बजट भी आबंटित करना चाहिये।

शासन प्रशासन को इनका ध्यान रखना चाहिये ।एक बार एक प्रकृति प्रेमी ने अनुग्रहपूर्वक अपने घर के आगे की सड़क के सारे गड्ढों में मिट्टी भरकर पेड़ लगा दिए तो यही वृक्षारोपण अभियान चलाने वाले उसके सारे पौधे उखाड़ कर ले गए और उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर गिरफ्तार करा दिया कि इसने सरकारी संपत्ति को अपना खेत समझ रखा है। अब सरकार तो खुद वर्षाकाल में अपनी ज़मीन पर पेड़ लगवाती है। यदि पेड़ लगे होते तो वहां पानी भरने की जगह पर वह अलग से दिखाई देते और किसी को गड्ढे में उतरने या गड्ढा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती ।पर सरकार भी कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ, और फिर दो दिन बाद और कुछ करने लगती है। सरकार की नीतियों में पता नहीं क्यों एकरूपता नहीं होती। वह आम आदमी और पूंजीपति देखकर बदलती रहती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये।

वर्षा काल में नालियों की सफाई न होने से नहीं अपितु वर्षा अधिक होने से कहीं-कहीं कमर तक पानी भर जाता है जिससे सड़कों पर ही नहरों की अनुभूति होने लगती है। कई शहरों में नौकायन का आनंद आने लगता है। फिर किसी को पिकनिक स्पाट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारी सुविधायें घर बैठे मिलने लगती हैं।नावों से सरकारी राशन मिलने से ये भावना और बलबती हो उठती है।

लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद आप नगर निगम वालों से सड़कों पर बने गडढ़ों की बाबत सवाल करो तो वह मासूमियत से यही कहते हैं कि यह गड्ढे पहले नहीं थे,यह तो बरसात का पानी भरने के बाद सड़क धंसने से नए बन गए हैं। हम वर्षाकाल समाप्त होते ही नया बजट मंगा कर इन्हें भरवा देंगे। लेकिन जब पहले ही दिन शहर में एक तीन साल की बच्चे, सात साल की लड़की और एक विवाहित युवक के गड्ढे में गिरकर कल कवलित होने की खबर आई तो मुझे लगा कि शहर वाले ये दो महीने भी कैसे निकालेंगे?

चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

आजाद जन्मे, आजाद जिए, आजाद मरे

1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपना नाम 'आजाद', अपने पिता का नाम 'स्वतंत्रता' और अपने निवास का नाम 'जेल' बताया। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई, जिसे आजाद ने बड़ी बहादुरी से सहा। कोड़े के हर वार पर उन्होंने 'भारत माता की जय' का नारा लगाया, जिससे उनकी दृढ़ता और साहस का परिचय मिलता है। चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी यात्रा काकोरी कांड से प्रारंभ होती है। यह वह समय था, जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां चरम पर थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। उस घटना में शामिल कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे। उसके बाद उन्होंने संगठन को फिर से मजबूत करने का बीड़ा उठाया।

23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन साहस, संघर्ष और बलिदान की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही साहसी और निडर थे, उन्हें अन्याय और अत्याचार बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके भीतर बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट-कूटकर थी और यही भावना आगे चलकर उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती रही। उनका प्रारंभिक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद कर लिया था। उनका बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता एक गरीब किसान थे और उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। चंद्रशेखर आजाद ने केवल 14 वर्ष की अल्पायु में ही स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया था। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपना नाम 'आजाद', अपने पिता का नाम 'स्वतंत्रता' और अपने निवास का नाम 'जेल' बताया। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई, जिसे आजाद ने बड़ी बहादुरी से सहा। कोड़े के हर वार पर उन्होंने 'भारत माता की जय' का नारा लगाया, जिससे उनकी दृढ़ता और साहस का परिचय मिलता है। चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी यात्रा काकोरी कांड से प्रारंभ होती है। यह वह समय था, जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां चरम पर थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। उस घटना में शामिल कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे। उसके बाद उन्होंने संगठन को फिर से मजबूत करने का बीड़ा उठाया। 1928 में उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। संगठन ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें काकोरी ट्रेन डकैती, लाहौर षडयंत्र मामला और केंद्रीय विधान सभा बमबारी शामिल हैं। काकोरी ट्रेन डकैती इस संगठन की सबसे प्रसिद्ध गतिविधियों में से एक थी। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन को लूट लिया था। उस डकैती का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय क्रांतिकारी अभी भी सक्रिय हैं।

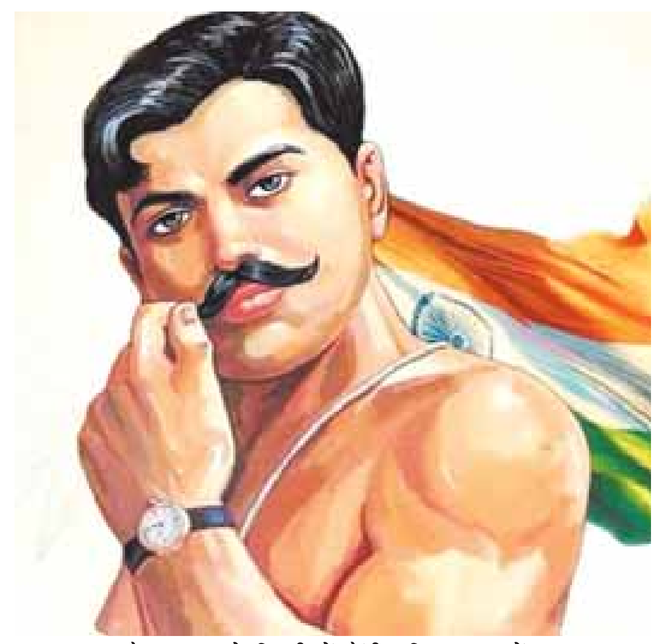

चंद्रशेखर आजाद ने न केवल क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया बल्कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित अनेक क्रांतिकारियों को प्रेरित भी किया। वे संगठन के भीतर अनुशासन और निष्ठा को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास किए और ब्रिटिश सरकार को कई बार चकमा देने में सफल रहे। 1928 में लाहौर षडयंत्र मामला हुआ था। उस मामले में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को बचाने की अथक कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बमबारी को हुई थी। उस घटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फैंके। उस बमबारी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय क्रांतिकारी अभी भी अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जब छोटे थे तो उन्होंने एक दिन एक बैलगाड़ी को पलटते हुए देखा। उन्होंने बिना किसी डर के बैलगाड़ी को सीधा करने में मदद की। अपने क्रांतिकारी कार्यों के लिए चंद्रशेखर आजाद अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर साइकिल से यात्रा किया करते थे, जो उनकी सादगी और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए वे अक्सर छद्मवेश धारण किया करते थे। एक बार पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने अपनी घनी मूंछें मुड़वा ली और भेष बदलकर वाराणसी चले गए। वहां उन्होंने साधु का रूप धारण कर लिया और ब्रिटिश पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी।

आजाद जब पुलिस से बचने के लिए अलग-अलग वेशभूषा अपनाते थे, तब एक बार वे साधु का वेश धारण कर एक मंदिर में शरण लिए हुए थे। अंग्रेज पुलिसकर्मी उन्हें पहचान नहीं सके और वे सुरक्षित बच निकले। इसी प्रकार, एक बार वे बनारस के एक घाट पर नाविक बनकर ब्रिटिश जासूसों को धोखा देने में सफल रहे। उनकी बुद्धिमानी और तेजतर्रार स्वभाव के कारण ही वे कई बार अंग्रेजों के हाथ आने से बच गए। उन्होंने विभिन्न व्यवसायों और सामाजिक वर्गों के लोगों के रूप में स्वयं को प्रच्छन्न किया। चंद्रशेखर आजाद एक उत्कृष्ट निशानेबाज थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही निशानेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया था और कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। उनमें अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वह एक ऐसे सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और देश के लिए अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाये। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ अपनी अंतिम मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। अपने साथियों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी भी जीवित ब्रिटिश पुलिस के हाथों नहीं आएंगे। अपने जीवन के अंत में भी उन्होंने इस प्रतिज्ञा का पालन किया और अपनी ही गोली से शहीद हो गए। उनके पास सीमित गोलियां थी लेकिन उन्होंने वीरता और चतुराई से अंग्रेज पुलिस का मुकाबला किया। अंततः जब उनके पास एकमात्र आखिरी गोली बची तो उन्होंने उसे स्वयं पर चला लिया ताकि वे अंग्रेजों के हाथ न लग सकें। उनका वह साहसिक निर्णय उनकी अटूट देशभक्ति का प्रतीक बन गया। अपने साहस, बलिदान और देशभक्ति से चंद्रशेखर आजाद ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और उनका बलिदान आज भी प्रत्येक भारतवासी को प्रेरित करता है। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, बलिदान और आदर्शों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने संकल्प को कभी टूटने नहीं दिया और आखिरी सांस तक अपने नाम 'आजाद' को सार्थक बनाए रखा। उनका जीवन और बलिदान आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। उनका नारा 'मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद मरूंगा' आज भी लोगों को प्रेरित करता है।

दतिया उपचुनाव

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

कोई भी जीते, हारेंगे नरोत्तम

दतिया में मतदान सन्निकट है। कहने को यह चुनाव दोनों प्रमुख दलों - कांग्रेस और भाजपा के बीच हो रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने आमने-सामने की सीधी लड़ाई को पेचीदा त्रिकोणीय संघर्ष में बदलकर हार-जीत के समीकरणों को गड़बड़ा दिया है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव के पेशगी तैयारी से मैदान में उतरने से संशय गहरा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सजातीय होने से अनेक लंतरानियां हवा में तैर रही हैं। चुनावी ऊंट की करवट को दादा (नरोत्तम मिश्र) की मौन 'मनौती' से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसे हरेक अपने-अपने तरीके से बूझ रहा है। वस्तुतः डॉ. नरोत्तम मिश्र की स्थिति तलवार की धार पे धावनों सरीखी हो गयी है। बीजेपी की जय और पराजय दोनों ही स्थितियों में उनके लिये नफा, कम, नुकसान ज्यादा का खतरा सन्निहित है।

डॉ. नरोत्तम मिश्र इस सामंती इलाके में च्दादाज्ञ के संबोधन से नवाजे जाते हैं। यह संबोधन उनकी हैसियत और छवि दोनों की चुगली करता है। इसमें आदर और दबंगई का ऐसा घोल है, जिसमें दोनों को पृथक्कृत नहीं किया जा सकता। इलाके में उनकी लोकप्रियता भी है और दबदबा भी। वह पारिवारिक प्रसंगों से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक समारोहों में शिरकत करते रहे हैं। उन्होंने 'अपनों' को कृतार्थ किया तो बैरियों को 'सबक'सिखाया।

हाजिरजवाबी और शेरोशायरी से वह जलसों और महफिलों की शान रहे। पार्टी के लिये वह च्संकटमोचनज्ञ रहे। उनकी साधन संपन्नता कइयों की ईर्ष्या का विषय बनी। दिल्ली के सत्ता सौध में वह एक अत्यंत प्रभावशाली नेता की च्नाक का बालज्ञ रहे और दिलचस्प तौर पर उन्होंने अपनी नाक के बालों का भी भरपूर खयाल रखा। कमलनाथ-सरकार को गिराने में भी उनकी नेपथ्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपने बयानों से वह सुर्खियों में रहे और आचरण से विवादास्पद। सूबे का सीएम बनने की उनकी महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं रह सकी। यही वे सन्दर्भ हैं, जो डॉ. नरोत्तम मिश्र को सत्तारूढ़ बीजेपी में अद्वितीय या विशिष्ट बनाते हैं। यही विशिष्ट नरोत्तम इस बार दतिया के उपचुनाव में टिकट से वंचित रहे। दादा का बेटिकट होना दादा के समर्थकों को कितना नागवार गुजरा,

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सजातीय होने से अनेक लंतरानियां हवा में तैर रही हैं। चुनावी ऊंट की करवट को दादा (नरोत्तम मिश्र) की मौन 'मनौती' से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसे हरेक अपने-अपने तरीके से बूझ रहा है। वस्तुतः डॉ. नरोत्तम मिश्र की स्थिति तलवार की धार पे धावनों सरीखी हो गयी है। बीजेपी की जय और पराजय दोनों ही स्थितियों में उनके लिये नफा, कम, नुकसान ज्यादा का खतरा सन्निहित है।

यह बीजेपी के नये नवेले उम्मीदवार के नाम का ऐलान होते ही जगजाहिर हो गया। दादा नहीं तो कोई नहीं की रौ में दादा के उग्र समर्थकों ने खूब बवाल काटा। और दादा...? बेबसी में दादा की आंखों में आंसू तिर आये। अब दादा कुछ बोलें या मौन रहें, मगर ये अबोले आँसू मुखर होकर गुल खिला रखे हैं। उनकी यह बबसी और मायूसी उनके समर्थकों को इस कदर साल रही है कि उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। दतिया में सामान्य वर्ग में ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक हैं। यह बैंक पहले विभाजित था, किंतु नये परिप्रेक्ष्य में तकरीबन पूरा समुदाय बीजेपी के हाथों से छिटक गया है।

दादा नरोत्तम इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं हैं। न तो वह दलीय प्रत्याशी हैं और न ही निर्दल, लेकिन चुनावी-दंगल में उनकी मौजूदगी महसूस की जा रही है। पार्टी ने उनकी गति सांप-छछूंदर सी कर दी है। सुविचारित रणनीति के तहत उन्हें चुनाव प्रचार की कमान सौंपा दी गयी है। कमेटी में इस्तीफा दे चुके उनके समर्थक पदाधिकारी भी हैं। पार्टी के लिये दादा को तन-मन-धन झोंकना होगा। हालाँकि, संभावना नगण्य है, किंतु फर्ज कीजिये कि बीजेपी के आशुतोष जीत जाते हैं, तो सेहरा किसके सिर बँधेगा? पार्टी नेतृत्व की जय-जयकार होगी और स्थानीय राजनीति में दादा हाशिये में सरक जायेंगे। अगले चुनाव में उनका दावा भी कमजोर होगा। यदि उन्हें कोई निगम-मंडल सौंपा भी गया तो उससे उनके रूतबे की भरपाई न होगी। और अगर्चे बीजेपी दतिया का दंगल हारती है, तो ठीकरा दादा के सिर फूटेगा। ऐसे में दादा तिरस्कृत और दंडित होंगे। अवधेश नायक की सक्रियता से कांग्रेस को बल मिला है और विभिन्न नेताओं के बयानों से दादा की निष्ठा संदिग्ध हो रही है। ऐसा नहीं है कि दादा इसे समझ नहीं रहे हैं, मगर वे निरूपाय हैं। उनके ग्रहयोग बुरे चल रहे हैं। दिल्ली के उनके आका भी उनकी टिकट बचा नहीं सके। एक नामालूम सा स्वयं सेवक बाजी मार ले गया। अब दतिया है, दादा हैं और चुनाव हैं। गत चुनाव में दादा करीब सात हजार मतों से हारे थे और करीब इतने ही वोटर एसआईआर में लिस्ट से हटाये गये थे। जब वक्त बुरा हो तो धार्मिक टोटके काम नहीं आते। यह अकारण नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया में जिताने का जिम्मा लेने से इंकार कर दिया। अब दंगल में उतरे तेईस मल्लों में से जीते कोई एक, मगर दंगल नहीं लड़कर भी हारेंगे दादा नरोत्तम।

आँखों-देखी

दिल्ली से लौटकर अजमत

जंतर-मंतर की एक रात और भारत की एक सुबह

दिल्ली से लौटने के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, 'वहाँ क्या हुआ?' मैं उन्हें घटनाएँ तो बता सकता हूँ, लेकिन जो मैंने वहाँ महसूस किया, उसे शब्दों में पूरी तरह बाँध पाना आसान नहीं है। शरीर पर लगी चोटें शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएँ, लेकिन मन पर जो चोट लगी है, उसे भरने में समय लगेगा। इसलिए यह किसी आंदोलन का समाचार नहीं है, न किसी पक्ष या विपक्ष का तर्क। यह एक नागरिक की आँखों-देखी है– उस भारत की, जिसे मैंने जंतर-मंतर की सड़कों पर देखा।

मैं दिल्ली किसी राजनीतिक दल की रैली में शामिल होने नहीं गया था। मैं उन युवाओं के बीच जाना चाहता था, जो देश के अलग-अलग हिस्सों से अपनी शिक्षा, अपने भविष्य और अपने अधिकारों की आवाज़ लेकर जंतर-मंतर पहुँच रहे थे। मेरे मन में उत्सुकता थी कि आखिर ऐसा क्या है जिसने हजारों युवाओं को बिना किसी बड़े नेता, बिना किसी राजनीतिक दल और बिना किसी संगठन के आदेश के एक मंच पर खड़ा कर दिया।

जंतर-मंतर पहुँचते ही सबसे पहले जिसने मेरा ध्यान खींचा, वह भीड़ नहीं थी, बल्कि उस भीड़ का स्वभाव था। चारों तरफ़ युवा ही युवा थे। कोई बिहार से आया था, कोई तमिलनाडु से, कोई पंजाब, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश, कोई उत्तर प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, कोई झारखंड, कोई बंगाल, तो कोई असम से। भाषाएँ अलग थीं, पहनावा अलग था, बोलने का अंदाज़ अलग था, लेकिन उनकी आँखों में एक जैसी चमक थी–उम्मीद की चमक।

भीड़ के बीच चलते-चलते मेरी नज़र एक पोस्टर पर जाकर ठहर गई। उस पोस्टर में महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर, शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक साथ दिखाई दे रहे थे। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था– 'इंकलाब ज़िंदाबाद।' मैं कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। बचपन से हमने इतिहास को टुकड़ों में पढ़ा। राजनीति ने भी अक्सर हमें यही सिखाया कि गांधी अलग हैं, भगत सिंह अलग हैं, आंबेडकर अलग हैं और सुभाष अलग हैं। लेकिन उस दिन जंतर-मंतर में खड़े युवाओं ने मुझे इतिहास का दूसरा अर्थ समझाया। उनके लिए गांधी सत्य और अहिंसा थे, आंबेडकर न्याय और संविधान थे, भगत सिंह साहस और सवाल थे और सुभाष आत्मसम्मान और स्वतंत्रता थे। चारों की राहें भले अलग रही हों, लेकिन मंज़िल एक ही थी–एक बेहतर भारत। उस पोस्टर ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मुझे लगा कि राजनीति जिन लोगों को वर्षों से अलग-अलग खेमों में बाँटती रही, नई पीढ़ी उन्हें फिर से एक साथ जोड़ रही है।

शाम धीरे-धीरे रात में बदल गई। दिल्ली की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं, लेकिन उन हजारों युवाओं के लिए न रहने की कोई व्यवस्था थी और न खाने की। बहुत-से लोग पूरे दिन सिर्फ़ पानी पीकर बैठे रहे। कुछ के पास बिस्कुट थे, कुछ के पास सूखा चना, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी पानी भी भोजन बन जाता है और फुटपाथ भी बिस्तर।

रात गहराती गई। मैं अपने साथियों के साथ जंतर-मंतर की गलियों में चलता रहा। थकान जब बहुत ज़्यादा हो जाती, तो किसी पेड़ के तने या किसी दीवार का सहारा लेकर कुछ देर कमर सीधी कर लेता। वही हमारी रात का विश्राम था। फिर उठकर लोगों के बीच चला जाता। उस पूरी रात मैंने किसी को शिकायत करते नहीं देखा। मैंने देखा कि एक युवक अपने बैग से पानी निकालकर बिल्कुल अनजान साथी को दे रहा है। कोई हाथ के पंखे से दूसरे को हवा कर रहा है। किसी ने अपने पास बचा हुआ बिस्कुट चार हिस्सों में बाँट दिया। एक लड़की अपने दुपट्टे से दूसरी लड़की का पसीना पोंछ रही थी। कोई कह रहा था, 'भाई, इधर आ जाओ, यहाँ थोड़ी जगह है।'

वे एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे। न किसी ने नाम पूछा, न धर्म, न जाति, न भाषा। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि जब कोई साझा उद्देश्य लोगों को जोड़ता है, तब पहचानें छोटी पड़ जाती हैं। वहाँ कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था। वहाँ केवल इंसान थे और उन सबकी सबसे बड़ी पहचान थी–वे भारत के नागरिक थे। रात बीत गई। शायद हममें से किसी ने ठीक से नींद भी नहीं ली थी। कोई फुटपाथ पर बैठा-बैठा ऊँघ गया था, कोई अपने बैग को तकिया बनाकर लेट गया था। सुबह होते ही फिर हलचल शुरू हो गई। चाय की छोटी-छोटी दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी। कोई चाय पी रहा था, कोई घर फोन करके सिर्फ़ इतना कह रहा था– 'हाँ, मैं ठीक हूँ।' युवाओं के छोटे-छोटे समूह फिर से इकट्ठा होने लगे। कोई संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा था। कोई गीत गा रहा था। कोई नारे लगा रहा था– 'शिक्षा हमारा अधिकार है', 'संविधान ज़िंदाबाद', 'इंकलाब ज़िंदाबाद।' इन नारों में गुस्सा कम था, उम्मीद ज़्यादा थी।

मैं भीड़ के बीच घूम रहा था। लोगों से बात कर रहा था। उनके चेहरे पढ़ रहा था। मुझे बार-बार गांधी का सत्याग्रह याद आ रहा था। गांधी कहते थे कि सत्याग्रह विरोधी को हराने का नहीं, बल्कि उसके विवेक को जगाने का प्रयास है। मुझे लगा कि ये युवा भी अपने तरीके से यही कर रहे थे। वे हिंसा नहीं, संवाद चाहते थे।

लेकिन शायद परिस्थितियों ने कोई और रास्ता चुन रखा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि पुलिस की हलचल अचानक बढ़ गई। बैरिकेड और सघन कर दिए गए। माहौल में एक अनकही बेचैनी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण कुछ होने वाला है। फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का समय ही नहीं मिला।

पहले धक्का-मुक्की हुई। फिर अचानक आँसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ ही क्षणों में धुएँ का घना गुबार पूरे इलाके में फैल गया। आँखों में तेज़ जलन होने लगी, साँस लेना मुश्किल हो गया। लोग अपनी आँखें मलते हुए इधर-उधर भागने लगे। कोई पानी खोज रहा था, कोई अपने साथी को ढूँढ़ रहा था। कुछ लोग पानी की बोतलों से एक-दूसरे की आँखें धो रहे थे। किसी ने अपना गमछा भिगोकर अनजान युवक के चेहरे पर रख दिया। चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल था।

मैंने पहली बार इतने करीब से आँसू गैस का असर देखा। टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले दृश्य और अपनी आँखों से देखे गए दृश्य में कितना अंतर होता है, यह उस दिन समझ में आया।

लेकिन जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया, वह केवल आँसू गैस नहीं थी।

मैंने अपनी आँखों से देखा कि कई युवतियाँ भगदड़ में गिर गईं। उन्हें सँभलने का भी मौका नहीं मिला। पुलिस के डंडे लगातार चल रहे थे। मैंने कई युवाओं को सिर, पीठ और कंधों पर डंडे खाते देखा। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि भीड़ को केवल पीछे हटाया जा रहा है; दृश्य इतना तीखा था कि कई लोगों के मन में भय साफ दिखाई दे रहा था। एक ओर डंडे चल रहे थे और दूसरी ओर आँसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। धुएँ और भगदड़ के बीच लोगों के लिए सुरक्षित दिशा में निकल पाना भी कठिन हो गया था।

उस अफरा-तफरी में मैंने कई ऐसे पुलिसकर्मियों को भी देखा जिनके नाम-पट्ट (बैज) दिखाई नहीं दे रहे थे। भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो वर्दी में नहीं थे, लेकिन हाथों में डंडे लिए हुए थे। उस समय यह समझ पाना मुश्किल था कि कौन किस भूमिका में है। मेरे सामने कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। किसी के हाथ में चोट थी, किसी के पैर में, कई लोगों की पीठ और सिर पर डंडों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लोग एक-दूसरे को उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा रहे थे। वहाँ उस समय सबसे बड़ी पहचान घायल और मददगार की थी।

कुछ समय बाद स्थिति थोड़ी शांत हुई। लोग इधर-उधर बिखरे हुए थे। किसी की आँखें लाल थीं, किसी के कपड़ों पर धूल जमी थी, किसी के चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी।

उस दिन मैंने न जाने कितने युवाओं से बात की। कोई किसान का बेटा था, कोई मज़दूर का, कोई पहली बार अपने गाँव से निकलकर दिल्ली आया था। उनके सपने अलग थे, लेकिन चिंता एक थी। भीड़ में कुछ लोग अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर रहे थे। किसी ने कहा, 'ऐसा लगता है जैसे देश डर के माहौल की ओर बढ़ रहा है।' किसी दूसरे युवक ने कहा, 'लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए।' मैं इन बातों को सुन रहा था, क्योंकि लोकतंत्र केवल संसद की बहसों से नहीं बनता, वह नागरिकों की आवाज़ों से भी बनता है।

दिल्ली से लौटने के बाद कई रातों तक मुझे ठीक से नींद नहीं आई। जैसे ही आँखें बंद करता, जंतर-मंतर का वही दृश्य फिर से सामने आ खड़ा होता। फुटपाथ पर बैठे युवा, धुएँ से भरा आसमान, भागते हुए लोग, किसी की आँखों में डाला जा रहा पानी, किसी घायल को सहारा देकर उठाते हाथ, और उन सबके बीच एक अनकहा विश्वास कि हम एक-दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई बार लगा कि मैं दिल्ली से लौट आया हूँ, लेकिन मेरा मन अब भी वहीं कहीं जंतर-मंतर की उस सड़क पर बैठा है।

दिल्ली से लौटते समय मेरे बैग में कोई पोस्टर नहीं था, कोई झंडा नहीं था, कोई नारा भी नहीं था। लेकिन मेरे भीतर अनगिनत चेहरे थे, अनगिनत आवाज़ें थीं और अनगिनत सवाल थे। बार-बार वही तस्वीरें आँखों के सामने आ रही थीं–फुटपाथ पर बैठा एक युवक, जो अपनी आधी बोतल का पानी किसी अनजान साथी को दे रहा था; वह पोस्टर, जिसमें महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक साथ दिखाई दे रहे थे; आँसू गैस के धुएँ के बीच एक-दूसरे को बचाने के लिए दौड़ते युवा; घायल साथियों को अपने कंधों का सहारा देते लोग; और भगदड़ के बीच भी इंसानियत का हाथ थामे खड़े अनगिनत चेहरे।

मैं जंतर-मंतर से कोई जीत या हार लेकर नहीं लौटा। मैं वहाँ से कोई राजनीतिक निष्कर्ष लेकर भी नहीं लौटा। मैं वहाँ से भारत को देखकर लौटा हूँ–एक ऐसा भारत, जो भूखा हो सकता है, थका हुआ हो सकता है, आँसू गैस से जिसकी आँखें लाल हो सकती हैं, लेकिन जो किसी अनजान व्यक्ति को पानी पिलाना नहीं भूलता। अगर भारत को समझना हो, तो कभी-कभी इतिहास की किताबों से ज़्यादा जंतर-मंतर की एक रात काफ़ी होती है। क्योंकि उस रात मैंने जाना कि भारत केवल एक भूगोल नहीं है; भारत उन लोगों का नाम है, जो कठिन समय में भी एक-दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। और उसी सुबह, दिल्ली से लौटते हुए, मुझे लगा–भारत अभी भी ज़िंदा है।

सोहागपुर गौरवान्वित, गौरव अग्रवाल प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी नियुक्त

सोहागपुर। राजेंद्र वार्ड निवासी युवा समाजसेवी गौरव अग्रवाल मोंटू भैया को प्रदेश भाजपा ने उनको प्रदेश मध्यप्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से सोहागपुर गौरवान्वित हुआ है।उल्लेखनीय है कि श्री मोंटू अग्रवाल वरिष्ठ

समाजसेवी कन्नूलाल अग्रवाल के सुपुत्र हैं। उनकी इस नियुक्ति पर नगर में हर्ष व्याप्त है। क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह,नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल, वरिष्ठ वकील जेपी माहेश्वरी, समाजसेवी अभय खंडेलवाल, प्रतिपालसिंह खनूजा पप्पू भैया, समाजसेवी विशाल गोलानी, व्यापारी संघ अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, राजेन्द्र वार्ड पार्षद गौरव पालीवाल , यश खंडेलवाल, समाजसेवी संजय खंडेलवाल, विजय छाबड़िया नन्नू भैया,राजा अग्रवाल,चिन्टू अग्रवाल, मनोज, अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अभिषेक चौहान, सहित कई गणमान्य नागरिकों ने उनको बधाईयां दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ,प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री धीरज खंडेलवाल आदि का आभार व्यक्त किया गया है।

कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम डॉ. राठौर को ज्ञापन सौंपा

सोहागपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर को महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि हम कांग्रेस जनों की तरफ से आपका ध्यान देश में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहते है। जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने युवाओं के भविष्य, नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं एवं छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को

प्रमुखता से उठाया है। ऐसे जनहित के विषयों पर आवाज़ उठाने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना और जनता की समस्याओं को उठाना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का संवैधानिक अधिकार है। ब्लाक कांग्रेस कमेटी एवं नगर कांग्रेस कमेटी इस अवैधानिक कार्रवाई का लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करती है । इसके साथ मांग करती है । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए तथा लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं जंतर मंतर में छात्रों के आन्दोलन में की जा रही केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के स्तीफे की मांग की गई है। इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय को प्रेषित करने का आग्रह किया है।इस अवसर पर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर,नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल, कांग्रेस नेता हरगोविंद पुड़िया,सेवादल अध्यक्ष इरफान खान,राकेश चौधरी वकील देवाशु शर्मा करनपुर सरपंच आजादसिंह ठाकुर, राजकुमार,महेश साहू,नीरज चौधरी, वकील कार्तिक शर्मा, किसान कांग्रेस अध्यक्ष गणेश अहिरवार,ऋषभ दीक्षित कमलेश प्रजापति मालवीय आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे।

अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर ने शासकीय सांदीपनी सीएम राइज स्कूल का औचक निरीक्षण किया

सोहागपुर न्यूज़। अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर ने शासकीय सांदीपनि सीएम राइज स्कूल एवं शासकीय कन्या शाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर ने दोनों विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं के उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया । इसके साथ वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर की नियमित साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। इसी अवसर पर एसडीएम डॉ. राठौर ने विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर छात्र-छात्राओं से संवाद करके उनसे पढ़ाई तथा शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। आपने विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने तथा मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हुए किया। आपने सांदीपनि सीएम राइज स्कूल एवं कन्या शाला के प्रधानाध्यापकों को शिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा अनुशासित एवं स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए।

भोपाल शहर एवं भोपाल ग्रामीण क्षेत्र के 4 लाख 24 हजार 504 उपभोक्ताओं को जून माह में 5 करोड़ 78 लाख की छूट

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल शहर एवं भोपाल ग्रामीण क्षेत्र के कुल 4 लाख 24 हजार 504 उपभोक्ताओं को जून माह में 5 करोड़ 78 लाख रुपए की रियायत प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे योजना के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने बताया है कि कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सोलर ऑवर में बिजली उपयोग करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दिन के टैरिफ में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है।

आरएनटीयू में राष्ट्रीय छात्र अध्ययन यात्रा का भावपूर्ण समापन

देशभर के हिंदितर राज्यों से पहुंचे विद्यार्थियों ने अपनी संस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां

भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में विश्वरंग फाउंडेशन और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय छात्र अध्ययन यात्रा-2026 का मंगलवार को गरिमामय एवं भावपूर्ण वातावरण में समापन हो गया। नौ दिनों तक चली इस अध्ययन यात्रा में देशभर के हिंदितर राज्यों से आए छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान विद्यार्थियों को भारतीय भाषा, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की प्रतिकुलाधिपति एवं विश्वरंग फाउंडेशन की निदेशक डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलगुरु डॉ. रविप्रकाश दुबे रहे। विशिष्ट अतिथियों में कुलसचिव डॉ. संगीता जौहरी और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की सहायक निदेशक सुश्री तमन्ना रानी मौजूद रहीं।

समापन समारोह का सबसे आकर्षक और भावनात्मक पक्ष देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं। असम, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी अपने-अपने पारंपरिक परिधानों में मंच पर पहुंचे। विद्यार्थियों ने अपने राज्यों के लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, सांस्कृतिक गीत और लोक-संगीत प्रस्तुत कर सभागार को भारतीय सांस्कृतिक विविधता के रंगों से भर दिया। प्रत्येक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे वातावरण में उत्साह, उल्लास एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार हुआ।

कार्यक्रम की एक विशेष बात यह रही कि प्रत्येक राज्य के विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति का मंच संचालन स्वयं किया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने राज्य की संस्कृति, भाषा, परंपराओं और लोकजीवन का परिचय भी दिया। नौ दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई मंच संचालन कला, भाषा कौशल और आत्मविश्वास की झलक उनकी प्रस्तुतियों में स्पष्ट दिखाई दी।

समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने अध्ययन यात्रा के नौ दिनों के अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि यह यात्रा केवल शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि भारतीय संस्कृति, भाषाई विविधता, साहित्य, इतिहास और राष्ट्रीय एकता को निकट से समझने का एक अविस्मरणीय अवसर बनी। विद्यार्थियों ने रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, विश्वरंग फाउंडेशन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा आयोजन से जुड़े सभी शिक्षकों, समन्वयकों और स्वयंसेवकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां मिला स्नेह, मार्गदर्शन और आत्मीय वातावरण जीवनभर उनकी स्मृतियों में रहेगा।

इस अवसर पर अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स ने कहा कि यह अध्ययन यात्रा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, भाषाई विविधता और मानवीय मूल्यों को समझने की एक जीवंत प्रक्रिया रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे यहाँ से प्राप्त अनुभवों को अपने जीवन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में आगे बढ़ाएँ।

वहीं मुख्य अतिथि डॉ. रविप्रकाश दुबे ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति संवेदनशील नागरिक बनना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस अध्ययन यात्रा से प्राप्त अनुभव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय की सहायक निदेशक सुश्री तमन्ना रानी ने कहा कि राष्ट्रीय छात्र अध्ययन यात्रा ने विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को एक परिवार की तरह जोड़ दिया है। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में हिंदी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित करते हैं।

कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथियों द्वारा प्रमाण-पत्र, स्मृति-चिह्न (मोमेंटो) एवं गिफ्ट किट प्रदान किए गए। सम्मान प्राप्त करते समय विद्यार्थियों के चेहरों पर प्रसन्नता के साथ-साथ बिछड़ने की भावुकता भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कई विद्यार्थियों और शिक्षकों की आंखें नम थीं। वहीं आयोजकों ने भी सभी प्रतिभागियों, अतिथियों, शिक्षकों, समन्वयकों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। भारत माता की जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय छात्र अध्ययन यात्रा-2026 का यह समापन समारोह भारतीय सांस्कृतिक एकता, भाषाई सद्भाव, पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय एकात्मता का जीवंत उदाहरण बन गया। नौ दिनों की यह यात्रा विद्यार्थियों के लिए केवल एक अध्ययन कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवनभर संजोकर रखने वाला सांस्कृतिक और मानवीय अनुभव बन गई।

छात्रावास अधीक्षक को हटाने और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई के निर्देश

अंत्येष्टि सहायता में लापरवाही पर सचिव को निलंबित और रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने के निर्देश

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को प्रभातपट्टन विकासखंड के ग्राम गेहूंबारसा का भ्रमण कर पंचायत भवन में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने पेयजल, शिक्षा, बिजली, सड़क एवं अन्य जनसमस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति में आ रही समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घोघरी परियोजना से शीघ्र ही ग्राम में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। एक ग्रामीण की अंत्येष्टि सहायता राशि तीन माह से लंबित पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिन बुजुर्गों और बच्चों का ई-केवाईसी लंबित है, उनका अभियान चलाकर शीघ्र समाधान करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने ग्राम पंचायत की विकास कार्ययोजना के अनुरूप स्वीकृत कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने पर संबंधित उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं पंचायत भवन नियमित रूप से नहीं खुलने तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए।

छात्रावास और स्कूल का निरीक्षण, गुणवत्ता पर जताई नाराजगी- भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने छात्रावास एवं माध्यमिक शाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्रावास की नवीन इमारत शुरू होने में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण में नवीन छात्रावास भवन की निर्माण गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने छात्रावास अधीक्षक को हटाने तथा संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही छात्रावास तक पहुंच मार्ग को सीसी रोड से विकसित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने माध्यमिक शाला का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन किया। बच्चों की आधारभूत शिक्षा (फाउंडेशन लर्निंग) अपेक्षित स्तर से कमजोर पाए जाने पर उन्होंने शिक्षकों को नियमित अभ्यास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने ग्राम के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण कर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था शीघ्र पूर्ण कर केंद्र का संचालन जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

राज्य में पांचवें स्थान पर आए छात्र गुंजन का बुक प्रकाशक कंपनी ने किया सम्मान

बैतूल। शहर के सबसे पुराने एवं प्रसिद्ध शासकीय स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल के छात्र गुंजन देशमुख के कक्षा दसवीं में राज्य व संभाग में पांचवे स्थान पर आने पर बुक प्रकाशक कंपनी शिवलाल अग्रवाल द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एक्सीलेंस स्कूल के प्रिंसिपल एसके उदयपुरे ने बताया कि शिवलाल अग्रवाल बुक प्रकाशक कंपनी के माध्यम से प्रति वर्ष कक्षा दसवीं में राज्य में पहले से पांचवे स्थान पर आने वाले विधथियों को अपनी तरफ से 5 हजार 100 रुपए की घोषित राशि देकर सम्मानित किया जाता है। इस साल एक्सीलेंस स्कूल के छात्र गुंजन पिता सुनील देशमुख ने राज्य में पांचवा स्थान हासिल किया। इस मौके पर बुक प्रकाशक कंपनी ने उन्हें उपरोक्त राशि का चेक देकर सम्मानित किया। यह सम्मान उनके पिता सुनील देशमुख ने लिया। इस अवसर पर बुक प्रकाशक कंपनी के डीलर घनश्याम शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल जीबी पाटनकर समेत एक्सीलेंस स्कूल का स्टाफ व विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक मौजूद थे।

भव्य महायज्ञ एवं श्री महालक्ष्मी देवालय स्थापना महोत्सव 23 जुलाई से

75 लाख के स्वर्ण आभूषणों से होगा माता का दिव्य श्रृंगार

भोपाल। करुणाधाम आश्रम, नेहरू नगर में 23 से 25 जुलाई 2026 तक श्री महालक्ष्मी देवालय के 11वें स्थापना महोत्सव के अवसर पर त्रिदिवसीय सार्वभौम दिग्विजय महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। तीन दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में देश-विदेश से श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, विशेष पूजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं विश्व शांति के लिए हवन होगा।

महायज्ञ में करुणाधाम के पीठाधीश्वर गुरूदेव श्री सुदेश जी शांडिल्य महाराज एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमां ममता शांडिल्य मुख्य यजमान के रूप में हवन में सहभागी होंगे। इस अवसर पर विश्व शांति, राष्ट्र की समृद्धि तथा भारत को विश्वगुरु बनाने की प्रार्थना की जाएगी। आयोजन के दौरान पूरे करुणाधाम परिसर को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया जाएगा। आयोजन का प्रमुख आकर्षण माता महालक्ष्मी का 75 लाख रुपये मूल्य के स्वर्ण हार एवं अन्य स्वर्ण आभूषणों से विशेष श्रृंगार रहेगा। माता को बहरीन से मंगवाई गई विशेष पोशाक धारण कराई जाएगी, जबकि श्रृंगार में उपयोग होने वाला स्वर्ण दक्षिण भारत से विशेष रूप से मंगवाया गया है। तीनों दिन माता का अलग-अलग दिव्य पोशाकों में श्रृंगार किया जाएगा। आश्रम के श्री शाश्वत शांडिल्य प्रतिदिन शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

ग्वालियर शहर एवं ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के 68 हजार 378 उपभोक्ताओं को जून माह में 1 करोड़ 12 लाख 87 हजार की छूट

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला सोलर ऑवर में 20 प्रतिशत छूट का लाभ

ग्वालियर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर शहर एवं ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के कुल 68 हजार 378 उपभोक्ताओं को जून माह में 1 करोड़ 12 लाख 87 हजार रुपए की रियायत प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे योजना के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया है कि कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सोलर ऑवर में बिजली उपयोग करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दिन के टैरिफ में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है। कंपनी ने बताया है कि घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य, स्ट्रीट लाइट एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि को सोलर ऑवर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उपभोग की गई ऊर्जा पर ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर में 20 प्रतिशत तक की छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही है। प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें तथा स्मार्ट मीटर के उपयोग से होने वाले लाभों का अधिक से अधिक फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से सटीक रीडिंग, पारदर्शी बिलिंग एवं ऊर्जा खपत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो रही है।

स्मार्ट मीटर के फायदे

- ऊर्जा की खपत को ट्रैक कर नियंत्रित करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है।
- बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती।
- एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं।
- ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं।
- ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन ट्रैक करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है।

ग्राम माछा नर्मदा तट पर सीड बाल वृक्षारोपण कार्यक्रम एसडीएम डॉ. बबीता राठौर के आतिथ्य में संपन्न

सोहागपुर। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा नर्मदापुरम के निर्देशानुसार जिलेभर में संचालित नवांकुर अभियान ,जन अभियान परिषद ने सोहागपुर अनुभाग के नर्मदा तट स्थित ग्राम माछा में सीड बॉल के माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम

अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर के आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष जालमसिंह पटेल, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे।

इस अवसर पर सीड बाल को नर्मदा नदी के विख्यात घाट के आस-पास विभिन्न उपयुक्त स्थानों ,राम जानकी मंदिर के निकट निर्मल विकास सेवा समिति प्रमुख प्रस्फुटन समितियों के सहयोग से करीबन 02 हजार सीड बाल फैलाकर अधिक से अधिक पौधौ के प्राकृतिक अंकुरित करने के उद्देश्य से डाले गए। जिससे

पर्यावरण संरक्षण में हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर के अलावा तहसीलदार शक्ति तोमर , नायब तहसीलदार राम सिपाही मरावी, जन अभियान परिषद के ब्लाक समन्वयक किशोर करोड़ोले, अनुराग तिवारी, भूपेंद्र ठाकुर,सालिकराम,सरवन, गोपाल ठाकुर, जितेंद्र कुमार, अरविंद केवट,जन अभियान परिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विद्यालय के छात्र-छात्राएं एवं ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। वहीं इस अभियान में स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में नवांकुर अभियान को सफल बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण में जनसहभागिता बढ़ाने का आह्वान किया है। ताकि नर्मदापुरम जिले में सीड बाल से बनने वाले पौधों से क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। इसी अवसर पर वक्ताओं ने शीट बाल का महत्व बतलाया गया कि जहां आम जन ना पहुंच सके जिस स्थान पर पहुंचना संभव ना ओर उस स्थान पर पानी की संभावना हो जानवरों के खाने की संभावना भी कम हो ऐसे स्थानो पर सीट वाल का सही उपयोग होता । परंतु हम मां नर्मदा के तट पर उनके संरक्षण में रहते है। अंत में विकास खंड समन्वयक किशोर करोड़ोले ने जय घोष नारो लगवाये गए । अंत में सभी छात्र छात्राओं को टाफी वितरण किया गया ।

संक्षिप्त समाचार

खाद्य प्रतिष्ठानों और मेडिकल स्टोरों का होगा सघन निरीक्षण

विदिशा (निप्र)। विदिशा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने जिले में आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन को खाद्य प्रतिष्ठानों एवं मेडिकल स्टोरों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से नियमित रूप से जांच अभियान चलाने तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आवश्यकतानुसार लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने यह निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभाकक्ष में आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के अंतर्गत की गई कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों द्वारा जिले में 19 निरीक्षण किए गए। जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर दो लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि एक लाइसेंस निरस्त किया गया। कलेक्टर ने भविष्य में भी इसी प्रकार नियमित निरीक्षण और प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए।

लंबित आवेदनों व विकास कार्यों की गहन समीक्षा

विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने तथा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। टीएल बैठक के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन की तैयारी, सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग, केंद्रीय मंत्री एवं प्रभारी मंत्री से प्राप्त पत्रों के निराकरण और उनके जवाब की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही स्कूलों, छात्रावासों एवं आईटीआई में प्रवेश की प्रगति का परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, श्रम विभाग, उद्यानिकी विभाग, खाद्य एवं औषधी प्रशासन, आबकारी विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति, जनजातीय कार्य विभाग सहित विभिन्न विभागो के कार्यो की समीक्षा की गई तथा ई ऑफिस फाइल पेन्डिग और न्यायालयीन प्रकरणो के कार्यो की भी समीक्षा की गई है। अधिकारियों से विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। बैठक में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली में लंबित फाइलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। न्यायालयीन प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को प्रभावी पैरवी करते हुए लंबित मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

दिव्यांग बसंत को घर पर मिली व्हीलचेयर

हरदा (निप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, हरदा द्वारा नवाचार के रूप में 'घर पहुँच सेवा' संचालित की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक माह ऐसे दिव्यांगजनों को चिन्हित किया जाता है, जो शारीरिक स्थिति अथवा गंभीर बीमारी के कारण विभागीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालय आने में असमर्थ होते हैं। उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, हरदा श्री कमलेश सिंह ने बताया कि इसी क्रम में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के विशेषज्ञों द्वारा श्री बसंत बरैया, पिता श्री जगन्नाथ, निवासी वार्ड क्रमांक 13, मानपुरा, हरदा का घर पर जाकर परीक्षण किया गया। चिकित्सकीय अनुशंसा एवं आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत उन्हें उनके निवास पर ही निःशुल्क व्हीलचेयर प्रदान की गई।

कलेक्टर ने जिला परिवहन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

जनहितैषी कार्यप्रणाली अपनाते हुए नागरिकों को त्वरित, सरल और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के कलेक्टर ने दिये निर्देश

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिला परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालय की व्यवस्थाओं, ऑनलाइन सेवाओं एवं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर, विभिन्न शाखाओं तथा अभिलेखों का अवलोकन किया और अधिकारियों को कार्यालय में स्वच्छ, व्यवस्थित एवं नागरिक हितैषी वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितैषी कार्यप्रणाली अपनाते हुए नागरिकों को त्वरित, सरल एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सारथी पोर्टल एवं वाहन पोर्टल पर संचालित ऑनलाइन प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन, परमिट, फिटनेस, कर भुगतान तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं के निष्पादन की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी ऑनलाइन आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए तथा नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करना पड़ें। उन्होंने कहा कि कार्यालय आने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ शालीन व्यवहार किया जाए तथा उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कार्यालय भवन के बेहतर संधारण, साफ-सफाई, अभिलेखों के व्यवस्थित रख-रखाव तथा आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों के लिये पेयजल, बैठने की व्यवस्था, सूचना बोर्ड एवं हेल्प डेस्क जैसी नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि परिवहन विभाग की सभी सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखें तथा शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें। लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जिले में नियमित रूप से वाहन जांच अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिना वैध दस्तावेजों के संचालित वाहनों, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस के साथ संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। साथ ही स्कूल वाहनों, यात्री वाहनों एवं व्यावसायिक वाहनों की नियमित फिटनेस जांच सुनिश्चित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन में जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

सावधान: सड़क पर खड़े वाहन को टो व्हीकल से उठाया जा सकता है

बेतरतीब खड़े वाहनों पर लगेगा व्हील लॉक, यातायात व्यवस्था सुधारने के लिये होगी सख्त कार्रवाई

समूचे जिले प्लास्टिक के उपयोग को किया जाएगा हतोत्साहित, स्वच्छता पर रहेगा विशेष जोरजिले में विद्युत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था हो : कलेक्टर

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने सोमवार को आयोजित समयावधि अंकित पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि हरदा नगर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़कों पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों पर 'व्हील लॉक' लगाया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऐसे वाहनों को 'टो व्हीकल' के माध्यम से हटाया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करें तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। बैठक में विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। ग्राम पंचायतों को भी अपने बकाया बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए गए, जिससे उनकी विद्युत व्यवस्था प्रभावित न हो। कलेक्टर ने अवैध खनिज उत्खनन के मामलों में आरोपित अर्थदंड की सख्ती से वसूली करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा

संबंधित विभागों को नियमित कार्रवाई करते हुए शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की भी साप्ताहिक समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को समय-सीमा में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने, शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा भी की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन, एसडीएम हरदा श्री अशोक डहेरिया, एसडीएम खिरकिया सुश्री रजनी वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

माँ का दूध शिशु की सुरक्षा का पहला टीका

सीहोर (निप्र)। माँ का दूध शिशु की सुरक्षा का पहला टीका है। यह शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक पोषक तत्व से परिपूर्ण होता है साथ ही शिशु में रोग-प्रतिरोधक क्षमता के विकास में सहायक है। सही समय में और उचित अवधि तक स्तनपान शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक होगा। माताएं जन्म के 1 घंटे के भीतर नवजात शिशु को स्तनपान प्रारंभ कर दें। नवजात शिशु जन्म से पहले छः माह तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। इसके बाद ही पूरक आहार की शुरूआत की जानी चाहिये। शिशु के 2 वर्ष होने तक स्तनपान जारी रखना चाहिये। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान की शुरुआत 41.3 प्रतिशत हुई है। यह एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में 6.9 प्रतिशत अधिक है। गर्भवती एवं धात्री माताओं को समुचित स्तनपान के लिए सहयोग प्रदाय किया जाता है एवं माताओं को दुग्ध दान के लिए प्रेरित किया जाता है। संग्रहित मानव दुग्ध, अस्पताल में भर्ती अत्यधिक कम वजन,प्रीमैच्युर एवं चिकित्सकीय जटिल नवजातों/अनाथ भर्ती शिशुओं के उपयोग में लाया जाता है।

कलेक्टर ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तहत क्रियान्वित कार्यों की समीक्षा की

जिले के 5090 विद्यार्थियों को 47981461 रुपए की राशि का भुगतान हुआ

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को आयोजित टीएल बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जिले के सभी विकासखंडों के छात्रावासों में विद्यार्थियों के प्रवेश की स्थिति तथा उपलब्ध सीटों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर आवासीय सुविधा का लाभ मिल सके। इसके लिए खंड स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान ग्राम वन समिति से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत विद्यार्थियों द्वारा कुल 6,167 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 5,500 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 5,090 विद्यार्थियों को योजना का लाभ देते हुए 4 करोड़ 79 लाख 81 हजार 461 रुपये की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है। कलेक्टर ने शेष पात्र आवेदनों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 6 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण प्रारंभ

विदिशा (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के क्षमता विकास एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से 8 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण के प्रथम बैच में जिले की 40 नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की अवधारणा, विभागीय योजनाओं, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों तथा मैदानी कार्यों के व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराना है, ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस पर प्रतिभागियों को आईसीडीएस की अवधारणा एवं उद्देश्यों, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात, कुपोषण के कारण एवं प्रकार, पोषण ट्रैकर एप के प्रभावी उपयोग, आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन, तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही समुदाय आधारित सेवाओं, पोषण जागरूकता एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इस प्रशिक्षण में विदिशा शहरी, विदिशा ग्रामीण, गंज बासौदा एवं त्योंदा परियोजनाओं की नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहभागिता कर रही हैं। आगामी दिनों में उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई), ग्रोथ मॉनिटरिंग, गृह भ्रमण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, विभिन्न विभागीय योजनाओं, अभिलेख संधारण, डिजिटल रिपोर्टिंग तथा समुदाय आधारित व्यवहार परिवर्तन संबंधी विषयों पर व्यवहारिक एवं सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षकों में महिला एवं बाल विकास विभाग से श्री अरविन्द मिश्रा, पर्यवेक्षक श्रीमती नीतू सोनी, श्रीमती सीमा शर्मा, श्रीमती संगीता सूर्यवंशी, श्रीमती नाहिद सुल्ताना एवं श्रीमती नेहा रघुवंशी शामिल हैं। विभाग का उद्देश्य इस प्रशिक्षण के माध्यम से नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दक्ष, संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाना है, जिससे जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा प्रारंभिक बाल विकास सेवाओं की गुणवत्ता में और अधिक सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

संयुक्त संचालक ने किया वन स्टॉप सेंटर एवं आंगनबाड़ी का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। महिला एवं बाल विकास भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक श्री हरिकृष्ण शर्मा ने सीहोर स्थित वन स्टॉप सेंटर और बिलकिसगंज स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां महिलाओं के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं की जानकारी ली और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, काउंसलिंग सहित समस्त सेवाएं नियमानुसार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्टर श्री जैन ने ली बैठक

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल एवं गरिमामय आयोजन को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय-सीमा में पूर्ण करने तथा विभागवार सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए। बैठक में समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था, मंच निर्माण, ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, साफ-सफाई, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर बेटी और परिवार के सदस्यों के चेहरों पर आई खुशी

विदिशा (निप्र)। गंजबासौदा निवासी आर्या दुबे के पिता श्री बाल कृष्ण दुबे सहायक शिक्षक का स्वर्गवास प्राथमिक शाला ग्राम पचमा ब्लाक गंज बासौदा से होने के उपरांत महिला बाल विकास के द्वारा श्री बालकृष्ण दुबे की पुत्री आर्या दुबे को सहायक ग्रेड 3 से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति विधिवत कार्यवाही कर की गई है। श्री बालकृष्ण दुबे शिक्षक की चार बेटियां थी जिसमें उनकी माता श्रीमती ज्योति दुबे द्वारा आर्या दुबे को अनुकंपा नियुक्ति हेतु लिखित सहमति व्यक्त की गई थी, जिसमें संपूर्ण जानकारी को बुलाने के उपरांत कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांसवा एवं स्थापना शाखा महिला बाल विकास विदिशा के द्वारा रुचि लेकर रिक्त पद महिला एवं बाल विकास परियोजना बासौदा 2 जिला विदिशा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति की गई ।

शासन की योजनाओं तथा विकास कार्यो का आमजन तक सुगमता से पहुंचे लाभ

टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाईन तथा योजनाओं की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन, विभागीय गतिविधियों, समय सीमा वाले पत्रों, योजनाओं तथा अभियानों की साप्ताहिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं, आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए! यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में जनकल्याणकारी और विकासमूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए सभी पात्र नागरिकों तक लाभ पहुंचाएं।बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभिन्न विभागों के समय सीमा वाले पत्रों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की तहसीलवार और अधिकारीवार समीक्षा करते हुए कहा कि शिकायतों का समयावधि में संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराएं। कोई भी शिकायत निम्न गुणवत्ता से बंद ना हो, यह सुनिश्चित कराएं।

इसी प्रकार सभी एसडीएम को विकासखण्डस्तर पर सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की मॉनीटरिंग करने के लिए कहा।बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने नगरीय निकायों में पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु पट्टा वितरण की कार्यवाही की जानकारी लेते हुए सभी सीएमओ से कहा कि पट्टा संबंधी प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करते हुए पात्रतानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाए। महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दलों के निरीक्षणों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले को कुपोषणमुक्त बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। इसी प्रकार आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला संयोजक को छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावासों में बच्चों को मीनू अनुसार नाश्ता और भोजन का वितरण सुनिश्चित कराएं। साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा बच्चों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण कराएं।कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण करें।

प्रदेश के लोड डिस्पैच सेंटर ने रचा नया कीर्तिमान, मिला अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन

सूचना एवं साइबर सुरक्षा में मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धि : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के जबलपुर स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए एसएलडीसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर का आईएसओ/आईईसी 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसे प्रदेश के विद्युत क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि देश के बड़े राज्यों के भार प्रेषण केंद्रों में एसएलडीसी जबलपुर इस प्रमाणन को हासिल करने वाले अग्रणी केंद्रों में शामिल हो गया है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दिल्ली स्थित क्वालिटी एशिया सर्टिफिकेशन द्वारा विस्तृत मूल्यांकन एवं ऑडिट के बाद यह प्रमाणन प्रदान किया गया है। ऑडिट में एसएलडीसी की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप

पाया गया। श्री तोमर ने कहा कि डिजिटल युग में विद्युत ग्रिड का संचालन पूरी तरह सूचना एवं संचार प्रणालियों पर आधारित है। ऐसे में साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और परिचालन सूचनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रमाणन इस दिशा में एमपी ट्रांसको की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पहले भी हासिल कर चुका है राष्ट्रीय पहचान

एसएलडीसी जबलपुर इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर चुका है। केंद्र को हाल ही में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। इसके अलावा आधुनिक ग्रिड प्रबंधन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऊर्जा प्रबंधन तथा अत्याधुनिक संचार प्रणालियों के प्रभावी उपयोग के कारण एसएलडीसी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। प्रदेश में बढ़ती विद्युत मांग के बीच सुरक्षित एवं निर्बाध ग्रिड संचालन सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

रियल टाइम ग्रिड ऑपरेशन से लेकर आईटी-ओटी सिस्टम तक हुआ मूल्यांकन

एसएलडीसी जबलपुर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रमाणन के दायरे में केंद्र के सभी नियमित एवं आउटसोर्स कार्मिक, प्रक्रियाएं तथा सूचना परिसंपत्तियां शामिल थीं। मूल्यांकन के दौरान रियल टाइम ग्रिड ऑपरेशन, विद्युत प्रणाली की शेड्यूलिंग, निगरानी एवं नियंत्रण, संचार नेटवर्क, आईएसडी एवं आईएसपी से जुड़ी गतिविधियों के साथ-साथ संपूर्ण ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (ओटी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सूचना सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन, साइबर सुरक्षा उपायों, डेटा संरक्षण और व्यवसाय निरंतरता व्यवस्थाओं को परखने के बाद ही यह प्रमाणन प्रदान किया गया है। इससे न केवल एसएलडीसी की कार्यप्रणाली को वैश्विक मान्यता मिली है, बल्कि मध्यप्रदेश की विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता और सुरक्षा भी और अधिक सुदृढ़ हुई है।

भोपाल में स्कूल बस चेकिंग

10 दिन के अभियान में 40 बसों में मिलीं सुरक्षा खामियां, ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान

भोपाल (नप्र)। राजधानी में स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग और लापरवाही की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच 10 दिनों का विशेष अभियान चलाया, जिसमें 40 स्कूल बसें सुप्रीम कोर्ट के तय सुरक्षा मानकों को तोड़ती पाई गईं।

जांच अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने शहर के अलग-अलग चौराहों और स्कूलों के बाहर 600 से अधिक स्कूल बसों को रोककर चेक किया। जिन बसों में कमियां पाई गईं, उनके मौके पर चालान काटे गए और गंभीर लापरवाही वाले मामलों को आरटीओ को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

अब प्राइवेट स्कूल वैनों की बारी

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यह 10 दिवसीय अभियान केवल स्कूल बसों पर केंद्रित था। अब जल्द ही शहर में चलने वाली ओमिनी, ऑटो और प्राइवेट वैनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें वैनों की ओवरलोडिंग, व्हीकल फिटनेस, परमिट, स्पीड गवर्नर और इमरजेंसी एग्जिट की कड़ाई से जांच होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन अपने ठेकेदारों की बसों की जांच खुद भी करें, वरना आरटीओ द्वारा परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

एमपी नगर और अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में ज्यादा कमियां

भोपाल के एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी और लालघाटी जैसे प्रमुख स्कूल बेल्ट में चली इस चेकिंग के दौरान ज्यादातर बसों में स्पीड गवर्नर बंद मिले और इमरजेंसी गेट पर सामान रखा पाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुनाफा कमाने के चक्कर में बच्चों की जान से जोखिम उठाया जा रहा है।

डॉ. हेडगेवार ने दिया था समानता का विचार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राष्ट्र, आज समान नागरिक संहिता का महत्व समझ रहा है

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने देशभक्ति के साथ समानता का दर्शन दिया था। वे भारत माता को मिलने जा रही स्वतंत्रता को कायम रखने के महत्व को पहले ही जान चुके थे, इस नाते उन्होंने राष्ट्र हित में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। वे दूरदर्शी सोच के साथ रचनात्मक प्रकल्प संचालित करते थे। डॉ. हेडगेवार के समता के भाव को आज राष्ट्र भी अंगीकार कर रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल भी इस भाव को दृष्टिगत रखते हुए की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रवींद्र भवन में संस्कार भारती द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने के अवसर पर हुए महानाट्य युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार के मंचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ईश्वर विशेष कार्य के लिए कोई निमित्त ढूंढता है। स्वामी विवेकानंद की ये भविष्यवाणी कि आने वाली सदी भारत की होगी,आज चरितार्थ हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, डॉ. हेडगेवार जी की कल्पना के भारत के निर्माण में संलग्न हैं। राष्ट्र अपने गर्व और गौरव को प्राप्त कर रहा है।भारत की पहचान एक विधान है। हमारा मूल दर्शन समानता का है। डॉ. हेडगेवार ने स्वतंत्रता के पहले चुनौती भरे दौर में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सर्वोपरि के भाव का प्रकटीकरण ही नहीं किया,लाखों लाख नागरिकों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कार भारती को डॉ. हेडगेवार के योगदान को नाटक के माध्यम से मंचित किये जाने के लिए बधाई दी। प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने का उल्लेख करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी गईं।

कार्यक्रम को राष्ट्रीय सेवक संघ के पदाधिकारी श्री हेमंत मुक्तिबोध ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्र को वैभव की ओर ले जाने के भरसक प्रयास किए। यह नाटक उनके जीवन के समर्पण,राष्ट्र निष्ठा और कर्म आधारित जीवन के स्वरूप को सामने लाने का माध्यम है। इस अवसर पर मंच पर वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अशोक पांडे, , फिल्म अभिनेता और रंगमंच निर्देशक श्री राजीव वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्री शशि भाई सेठ, पूर्व राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, संस्कृति संचालक श्री एन.पी. नामदेव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया गया। आभार प्रदर्शन श्री रविंद्र सहस्त्रबुद्धे ने किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नाटक के कलाकारों को उत्कृष्ट अभिनय के लिए बधाई दी। नागपुर की नादब्रम्ह संस्था द्वारा तैयार इस नाटक का निर्देशन श्री सुबोध सुरजीकर ने किया। नाटक के लेखक डॉ. अजय प्रधान हैं। संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से हुए नाटक में दक्ष कलाकारों ने प्रभावी अभिनय कर नाट्य प्रस्तुति को सफल बनाया। देश के अनेक नगरों में नाटक का मंचन हुआ है।

बच्चे बोले- पापा का पड़ोस वाली आंटी से अफेयर है

महिला आयोग से कहा- मम्मी से मारपीट करते हैं, डिप्रेशन में सुसाइड अटैम्प्ट कर चुकीं

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की मंगलवार की जनसुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें दो नाबालिग बच्चों ने अपने ही पिता के खिलाफ शिकायत की। बच्चों का आरोप है कि पिता का पड़ोस में रहने वाली आंटी से अफेयर है। विरोध करने पर वह मां के साथ मारपीट करते हैं। मां डिप्रेशन में हैं और आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी हैं।

एक अन्य मामले में फैक्ट्री हादसे में कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को मुआवजा नहीं मिलने पर आयोग ने कंपनी को अगली सुनवाई में हर हाल में हाजिर होने के निर्देश दिए।

पहले पढ़िए केस-1- पापा का चार साल से अफेयर चल रहा

दोनों बच्चे पिता की शिकायत लेकर पहुंचे। मां के लिए मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा- पापा का एक शादीशुदा महिला से पिछले चार साल से संबंध है। इस मामले की शिकायत थाने में कर चुके हैं, तब पापा ने शपथ पत्र देकर दोबारा ऐसा नहीं करने का भरोसा दिया था, लेकिन इसके बावजूद वह महिला के संपर्क में हैं।

बच्चों का आरोप है कि विरोध करने पर पापा

उनकी मां के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें भी पीटते हैं। लगातार घरेलू विवाद के कारण उनकी मां मानसिक रूप से परेशान हैं। उनका इलाज चल रहा है। वह डिप्रेशन की दवाइयां ले रही हैं।

बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित महिला के तीन बच्चे हैं। वह आंगनवाड़ी सहायिका है। महिला ने उनके पिता से पैसे भी लिए हैं, जो अब तक वापस नहीं किए हैं।

केस- 2- पति-पत्नी के बीच सुलह, दोनों साथ रहने को राजी

जनसुनवाई के दौरान एक पारिवारिक विवाद का भी निपटारा हुआ। महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी। दोनों पक्षों को सुनने और समझाइश के बाद आपसी सहमति से समझौता हो गया। महिला ने आगे कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही, जबकि पति ने भी आपसी सामंजस्य से रहने पर सहमति जताई।

केस-3-फैक्ट्री कर्मचारी की मौत, कंपनी को नोटिस

मंडीदीप स्थित एक फैक्ट्री के वेयरहाउस में गेहूं की बोरियों के नीचे दबने से एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। उसकी पत्नी ने महिला आयोग से मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। सुनवाई के दौरान कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इस पर आयोग ने कंपनी को अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि अगर अगली तारीख पर भी कंपनी का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ वारंट जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

घरेलू हिंसा, प्रताड़ना समेत 18 मामलों की सुनवाई

महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव, सदस्य साधना स्थापक और सचिव सुरेश तोमर की मौजूदगी में कुल 18 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद और मुआवजा से जुड़े मामलों में दोनों पक्षों को सुनकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

कर्ज से परेशान शेफ ने फांसी लगाई

सुसाइड नोट में लिखा- कर्ज चुका दिया, फिर भी रोज 10 हजार रुपए ब्याज मांग रहे

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में देर रात एक शेफ का शव पेड़ से फंदे पर लटका मिला। घटना कलियासोत डेम के पास तेरा शटर क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू की।

मृतक की पहचान बृजधाम कॉलोनी, नीलबड़ निवासी रामश्रवण पटेल (37) के रूप में हुई, जो कोलार रोड स्थित एक बंगले में शेफ का काम करता था। मौके से उसकी बाइक और पैंट की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था- परिजनों के मुताबिक रामश्रवण मंगलवार दोपहर घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। देर रात उसका शव कलियासोत डेम क्षेत्र में

पेड़ से लटका मिला। सुसाइड नोट में लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी।सूचना पर बुधवार सुबह पुलिस ने शव को फंदे से उतारा।

सुसाइड नोट में सूदखोर और रिकवरी एजेंट पर आरोप- सुसाइड नोट में रामश्रवण ने लिखा कि मकान निर्माण के लिए उसने बृज पटेल नामक व्यक्ति से 3.70 लाख रुपए उधार लिए थे। उसका दावा था कि वह पूरी मूल रकम चुका चुका है, लेकिन इसके बाद भी उससे रोजाना 10 हजार रुपए ब्याज की मांग की जा रही थी। उसने यह भी लिखा कि एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट भी लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। इसी मानसिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

भाई बोला- गहने गिरवी रखकर भी कर्ज चुकाया- मृतक के भाई अरुण पटेल ने बताया कि रामश्रवण ने कर्ज चुकाने के लिए परिवार के गहने तक गिरवी रख दिए थे। इसके बावजूद तकादेदार लगातार उसे परेशान कर रहे थे। परिवार के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से वह मानसिक रूप से बेहद तनाव में था।परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि तीन दिन पहले रामश्रवण को चुनाभट्टी थाने बुलाया गया था। वहां उसे घंटों बैठाकर कर्ज चुकाने का दबाव बनाया गया। हालांकि पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया।

आज मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में होंगे शामिल

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को देंगे श्रद्धांजलि, किसानों से करेंगे संवाद,340 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों की देंगे सौगात

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में उनकी 120वीं जन्म जयंती के अवसर पर कृषि उपज मंडी में 23 जुलाई 2026 को बलराम कृषि महोत्सव, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जन्मजयंती समारोह आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव चंद्रशेखर आजाद नगर में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली आजाद कुटिया पहुंच कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करेंगे।

दतिया उपचुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने डाले वोट, 30 जुलाई को होना है मतदान

दतिया (नप्र)। विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग का आगाज बुधवार से हो गया है। चुनाव आयोग की पहल पर दतिया क्षेत्र के 90 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता अपने घर से ही पहला वोट डालेंगे। 30 जुलाई को होने वाले मुख्य मतदान से पहले इन मतदाताओं के लिए विशेष पोलिंग टीमों का गठन किया गया है, जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोपनीयता के साथ वोट दर्ज कराएंगी।

अब तक 1.06 करोड़ का माल सीज- चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की टीमों ने सोमवार शाम तक चेकिंग के दौरान 1.06 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध नकदी, शराब और अन्य सामान जब्त किया है। शहर के प्रवेश मार्गों और अंतरराज्यीय सीमाओं पर बने चेक पोस्टों पर गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है।

30 जुलाई को होना है मुख्य मतदान- दतिया सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई को तय है। इससे ठीक पहले घर से वोट डालने की यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए दी गई है, जो शारीरिक रूप से पोलिंग बूथ तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

क्रांति ने अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया में बढ़ाया भारत का मान : मुख्यमंत्री

सीएम ने क्रांति गौड़ को दी 5 लाख रुपए सम्मान राशि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। राज्य में 'खेलो बढ़ो अभियान' के अंतर्गत सांसद कप, विधायक कप के माध्यम से प्रदेश के हर विधानसभा और तहसील स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य सरकार के इसी संकल्प का परिणाम है कि आज प्रदेश के खिलाड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट्स, ओलिम्पिक गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स में पदक जीत कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटों के साथ-साथ हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। मध्यप्रदेश की बेटी सुश्री क्रांति गौड़ ने अपनी प्रतिभा और कौशल के दम पर पूरे देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित संवाद भवन में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुश्री क्रांति गौड़ और उनके पिता श्री नरसिंह एवं भाई श्री महेन्द्र सिंह को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्रिकेटर सुश्री गौड़ को बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की लाड़ली बिटिया और हमारी छोटी बहन सुश्री क्रांति प्रदेश में नई खेल क्रांति लेकर आई हैं।